श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरडिया : वह कामराज प्लान है, यमराज प्लान है, कौन सा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यह जो यादवी फैल गई है उस यादवी की चर्चा विशेष रूप से न हो, दूसरे दलों की ओर लोग आकृष्ट न हों यदि उसकी चर्चा की जाय, इसको रोकने के लिये, उनकी ज़बान पर ताले लगाने की दृष्टि से और इस ख़याल से कि जो कांग्रेस की आपस की लड़ाई की वजह से व्हैक्यूम हो रहा है उसमें कोई और घुस नहीं आए, उस पर कलमबंदी के लिये, लेखनी पर प्रतिबंध लगाने के लिये, उसका विशेष उपयोग लिया जा रहा है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अगर हमारे कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के लोग आज भी इसके बारे में सिन्सियर हैं कि हमारे देश में संकट की स्थिति बनी रहनी चाहिये तो मैं उनसे ही प्रश्न करता हूं : क्या वे कभी अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हैं कि जितना संकटकाल के लिये हमें सन्नद्ध रहना चाहिये और उसके लिये हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिये और दैनिक जीवन में वैसा आचरण करना चाहिये, वैसा क्या हम कर रहे हैं ? वैसे तो यहां पर याजी जी अपनी झेंप मिटाने के लिए संभवतः कह दें कि हम बराबर कर रहे हैं। मगर दिल से पूछें तो संकट की स्थिति हमें . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

ANNOUNCEMENT *RE*: GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government business in this House for the week commencing 9th March, 1964, will consist of:

1. Further consideration and return of the Appropriation (Railways) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

2. Further consideration and passing of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1963, as reported by the Joint Committee of both Houses.

3. General Discussion on General Budget for 1964-65.

4. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following:—

   Demands on Account (General) for 1964-65.

   Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1963-64.

   Supplementary Demands for Grants (General) for 1963-64.

As the above business is not likely to be completed by 13th March, I suggest, Sir, that the House may be pleased to sit on Monday, the 16th March, and Tuesday, the 17th March, if necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

RESOLUTION *RE*: ENDING STATE OF EMERGENCY—*continued*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chordia.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभापति महोदय, मैं जो चर्चा कर रहा था उसमें इस बात पर प्रकाश डाल रहा था कि यह जो संकटकाल है तथा जो कांग्रेस में संकट उपस्थित हो गया है और उसको ठीक करने की दृष्टि से ही इस संकट को जारी रखना हमारी सरकार आवश्यक समझती है । यह स्वाभाविक है कि हमारे माननीय सदस्य चाहेंगे कि मैं इसके बारे में कुछ तथ्य रखूं, तो मैं उनके सामने वर्तमान के कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिससे उनको इस बात की तसल्ली हो जायेगी कि कांग्रेस का संकट टालने के लिए ही यह कोशिश हो रही है । इसका सीधा अर्थ यह है कि इस संकट को जारी रखने से आप लेखनी पर प्रतिबन्ध लगाये रखना चाहते हैं, बोलने पर प्रतिबन्ध लगाये रखना चाहते हैं और जिस तरह से कृष्ण भगवान् के सामने यादवों की खींचातानी चल रही थी वैसे ही हमारे प्रान्तों में इस समय चल रही है और उसी को टालने के लिए इस इमरजेंसी को रखा जा रहा है । विरोधी दलों को भी दबाने के लिए आप इस इमरजेन्सी के हथियार को अपने हाथ में रखना चाहते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि जब कन्नमवार महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री थे तो उस समय आचार्य अर्ते और नागपुर के दो पत्रकारों को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया ? जब कन्नमवार गये और नये मख्य मन्त्री आये तो उन्होंने इस खुशी में उन्हें छोड़ दिया । या तो इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया था या जिस तरह से पहले राजा महाराजा जब गद्दी पर बैठते थे तो इस खुशी में वे कैदियों को छोड़ दिया करते थे, उसी तरह से महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री जी ने भी अपनी खुशी में इन लोगों को छोड़ दिया । आचार्य अर्ते जी और नागपुर के जो दो पत्रकारों को पहले गिरफ्तार किया गया था क्या उनको पहले गिरफ्तार करना जस्टीफाइड कहा जा सकता है और फिर बाद में छोड़ देना भी जस्टीफाइड है ? मैं इन दोनों बातों का जवाब चाहता हूं ?

श्री एल० एन० मिश्र (बिहार) : दोनों बातें जस्टीफाइड हो सकती है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : क्योंकि आपकी इस समय ब्रूट मैजारिटी है इसलिए आप हर बात को जस्टीफाइड कह सकते हैं । आपकी जो मैजारिटी है उसमें जब तक कमी नहीं होगी आप दिन को रात कह सकते हैं और रात को दिन कह सकते हैं और यह दोनों चीजें आपके लिए जस्टीफाइड हैं । मगर आपको अपना दिल टटोलना चाहिये और अपने से पूछना चाहिये कि ओवर नाइट ही एक आदमी जो पहले कानून की खिलाफवर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया था उसे नये मुख्य मन्त्री के आते ही क्यों छोड़ दिया जाता है ? जब नये मन्त्री जी आये तो वे लोग जो पहले कानून विरोधी समझे जाते थे वे एक दम अच्छे बन जाते है ? इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसा आप बतलाते हैं कि हमारे देश में संकट है तो इस चीज को दृष्टि में रख कर सरकार को कार्य करना चाहिये । जो छोटे छोटे लोग या पत्रकार गिरफ्तार किये जाते हैं जो आपके लिटिल लिटिल नेहरू हैं, लिटिल लिलिटल लीडर हैं, वे स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और इस तरह की गड़बड़ करवाते हैं । इस तरह से इस कानून का दरुपयोग किया जा रहा है । हमारे देश में कुछ ऐसे संकुचित मनोवृत्ति के लोग हैं जो अधिकारियों से मिल कर अपना काम बनाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करवा रहे हैं । सतना में इस तरह के केसेज हुए हैं ।

दिल्ली में जो गुड़ काण्ड हुआ है उसकी भी काफी चर्चा है मगर इस कानून का प्रयोग ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं किया जाता है क्योंकि वे लो सत्तारूढ़ दल से सम्बन्ध रखते हैं । हमारे देश में संकटकाल की घोषणा की गई है और फिर भी कलकत्ते में इस तरह का काण्ड हुआ तो आपका डी० आई० आर० कहां चला गया था ?

श्री सी० डी० पांडे . दो दिन मे वहा सब चीज़ खत्म हो गई थी ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया · यह तो आप कलकत्ते वालों से पूछ सकते हैं जिनके ऊपर यह बात बीती । आज भी हमारे देश मे पंचगागियों की कमी नही है, प्रो पाकिस्तानियों की कमी नही है, प्रो चाइनीज की कमी नही है । आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संकटकाल की स्थिति को जारी रख कर आप डी० आई० आर० के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं । आज जनता के ऊपर टैक्स का भार बहुत बढ गया है और सारे लोगों के दिमाग में यह बात है कि चीजों के दाम दिन पर दिन बढते ही चले जा रहे है मगर आप सकटकाल की स्थिति को जारी रख कर उनकी जबान को बन्द कर देना चाहते है, उनकी लेखनी को बन्द कर देना चाहते है । हमारे जो सत्तारूढ दल के लोग है, मन्त्रिमण्डल के लोग है प्रमुख लोग है उनका व्यवहार संकटकाल की स्थिति की तरह नही लगता है । ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए कोई संकटकाल है ही नही । यह जो संकटकाल है वह जनता को दबाने के लिए ही है, उसको दबाने के लिए ही जारी रखा जा रहा है । अभी हमारे नन्दा जी ने अपना प्रवचन दिया तो क्या वे अपने सारे दल के लोगों को, अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से कहेगे कि वे संकटकाल की स्थिति को ध्यान में रख कर उसकी अनुभूति कर आचरण करे ? आज देश मे सचमुच सकटकाल की स्थिति पहले से ज्यादा गम्भीर हो गई है । यह कहना कि हम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गये हैं सिर्फ कह देने से नहीं हो सकते हैं । ऐसा मुझे लगता नहीं है कि देश में संकटकाल की स्थिति को ध्यान में रख कर काम किया जा रहा है अगर किया जाता तो आज हमारे यहां सैबोटेज के कार्य होते नहीं दीखते । नागपुर में आग लगी, कलकत्ते में हवाई जहाज हुगली नदी में नष्ट हो कर गिर पड़ा, परसों ही जम्मू काश्मीर में एक हवाई जहाज गिर पड़ा जिसका अभी तक पता नही चला । इससे पहले एक और हवाई जहाज जम्मू काश्मीर में तार से टकरा कर गिर पड़ा । क्या ये सब चीजे संकटकाल की घोषणा से ली अनुभूति के अभाव का परिणाम नहीं हैं ? ऐसा लगता है कि हमारा शासन सकट काल की जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुभूति नही कर रहा है । वह तो इस समय सारे प्रान्तों में अपने आपसी झगड़ों में ही पड़ा हुआ है । आज हमें इस बात का अहसास करना चाहिये कि देश में जो एयर क्रैश या दूसरी सैबाटेज की घटनाये हो रही हैं वे क्यों हो रही हैं और इनके पीछे किसका हाथ है ? हमें बीमारी की जड़ में जाना चाहिये सिर्फ बीमारी बीमारी कहने से काम नही चलेगा और न वह कम हो हो सकेगी । दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है और इस सकटकाल में भी हमें उसी तरह का आचरण करना चाहिये था मगर मुझे दुःख होता है कि शासक दल ने इसके अनुरूप कार्य नही किया । शासक दल ने देश में सकट की स्थिति की तो घोषणा कर दी मगर उसके अनुरूप उसने कोई कार्य नही किया । इसलिये मेरी इस सरकार से यह प्रार्थना है कि अगर वह सचमुच सकटकाल को महसूस करती है तो उसको अपना सारा आचरण उसके अनुरूप बनाना चाहिये । जनता को दबाने के लिये, किसी दल के लोगों को दबाने के लिये उसे कानून का दुरुपयोग नही करना चाहिये । दूसरे दल के लोगों को गिरफ्तार करके आपका सकटकाल टलने वाला नही है, आपको इन लोगों को छोड़ देना चाहिये । इस समय जो स्थिति है वह सकट की स्थिति नही प्रकट करती है, यह तो कांग्रेस का अपना संकट है और उसी को छिपाने के लिये संकट की स्थिति को जारी रखा जा रहा है । हमारी सरकार को इस सारी बात पर विचार करना चाहिये ।

आज सारे राष्ट्र में सकट है, मै इस बात को मानता हूं और स्थिति पहले से भी गम्भीर

होती जा रही है। मैं यह भी मानता हूं कि इसका कारण कांग्रेस की उपेक्षा की नीति है, तुष्टीकरण की नीति है, दब्बूपन की नीति है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज सरकार की नीतियों के ही कारण देश में संकट की स्थिति बनी हुई है। इसलिए में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज की जड़ पर जाये और उसको ठीक करे। इस तुष्टीकरण की नीति से काम चलने वाला नहीं है। हमारी जो शान्ति और तुष्टीकरण की नीति चलती आ रही है उसी से आज देश में संकट की स्थिति है और इससे काम चलने वाला नहीं है।

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Why don't you make peace?

SHRI C. D. PANDE: With whom?

SHRI P. N. SAPRU: With China.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: With aggressor he wants peace.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकटकाल में आपको अपना आचरण, अपने दल का आचरण ठीक रखना चाहिये। इस समय प्रान्तों में, वहां के शाहनशाहों में चीफ मिनिस्टरों में जो गड़बड़ी चल रही है उनसे भी आप कहें कि संकटकाल की स्थिति को देखते हुए उसी आचरण से काम करें। (*Interruption*) तारिक साहब भी खुश हो गये होंगे क्योंकि अब काश्मीर में उनकी अपनी सरकार बन गई है। अभी तक वे वहां की सरकार के खिलाफ बातें कहा करते थे लेकिन ओवरनाइट में सब कुछ बदल गया। जहां नया मंत्रिमंडल आया कि हमारे तारिक साहब अब काश्मीर के बारे में विशेष चर्चा नहीं करते हैं, नहीं तो पहले ऐसा था कि काश्मीर में यह गड़बड़ हो रही है, तो यह जो मनोवृत्ति है, इस मनोवृत्ति को हम ठीक नहीं समझते हैं। हम गलत को गलत कहेंगे, संकट की स्थिति को संकट मान कर चलेंगे, खराब स्थिति होगी तो खराब मान कर चलेंगे और अच्छी स्थिति होगी तो अच्छी मान कर चलेंगे। अगर यह शासन संकट की स्थिति मानता है तो यह मेरा नम्र निवेदन है कि वह उसके अनुसार आचरण करे, खुद सरकार उसकी अनुभूति और जनता भी उसकी अनुभूति करे। शासन ज्यादा अनुभूति करे तो ज्यादा अच्छा होगा। वरन् इस संकटकाल की स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो जनता पर भार पड़ रहा है, उससे एक व्यर्थ का टेंशन लोगों के दिमाग में बढ़ रहा है और अराजकता की भावना पैदा हो रही है। इसलिये या तो आप स्वयं अपना आचरण सुधारें या इस संकटकाल की स्थिति से मुक्ति ले करके भगवान का नाम लें या रघुपति राघव राजा राम जप करके संतोष करें। आधे मन से या दुतरफा सोचने से काम चलने वाला नहीं है। यही निवेदन है।

<u>شری اے - ایم - طارق</u> (جموں اور کشمیر) : میڈم ڈپٹی چیئرمین - جہاں تک اس ریزولیوشن کا تعلق ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں -

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : पूरी मुखालिफत तो नहीं करेंगे ?

<u>شری اے - ایم - طارق</u> : آدھی کروں گا لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جتنے نظر بند ہیں اس ملک میں اور کافی عرصہ سے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہئے - اگر وہ چھوڑے نہیں جا سکتے ہیں تو ان کے خلاف جو شکایتیں ہیں ان کو عدالت میں لانا چاہئے - اس سے ایک صورت یہ پیدا ہو جائے گی کہ ملک کے جو

اس وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے کہ چین اور پاکستان الگ الگ یا مل کر ہماری سرحدوں پر حملہ نہیں کرینگے اگر آج ہندوستان کو یہ ضمانت مل جائے کہ پاکستان اور چین ہندوستان کے علاقوں پر حملہ نہیں کرینگے اور پاکستان کے لوگ ہندوستان کی سرحدوں کے اندر گڑ بڑ کرنے کی کوشش نہیں کرینگے تو ایمرجنسی بذات خود ختم ہو جائیگی لیکن ان دونوں چیزوں کی ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے بلکہ اگر ہم دیانتدارانہ اور ایک ہندوستانی کی حیثیت سے یہ چھوڑ کرکے کہ ہم کسی جماعت کے اندر ہیں اس بات کو دیکھیں تو ہم کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں ایمرجنسی ہے -

میں مسٹر بھوپیش گپتا کی مخالفت اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ مختلف جماعت کے ممبر ہیں یا لیڈر ہیں اور انہوں نے یہ ریزولیشن پیش کیا ہے بلکہ میں نے اکثر موقعوں پر ان کی حمایت کی ہے اور میرے دوست آنریبل پانڈے یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا زیادہ ساتھی ہوں اور پانڈے صاحب کا کم ہوں - لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ملک کا معاملہ سامنے ہو تو اس میں افراد کی دوستی کے معنی کچھ نہیں رہتے - ملک کی اہمیت

[شری اے - ایم - طارق]

چاہے لوگ یا چاہے جماعتیں ڈیفنس آف انڈیا رولز کی مخالفت صرف اس لئے کرتی ہیں کہ اس موجودہ سرکار نے اسے لاگو کیا ہے ان کو لوگوں میں یہ غلط بات بولنے کا موقعہ نہیں ملے گا کہ ڈیفنس آف انڈیا رولز موجودہ حکومت نے صرف اپنے سیاسی فائدہ کے لئے لاگو کئے - بلکہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا اور ہمیں عوام کو بھی یہ بتانا ہے کہ ڈیفنس آف انڈیا رولز کی ضرورت اس ملک میں ہے ؟ تھی اور آگے بھی کچھ مدت کے لئے رہے گی - ایمرجنسی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں جنگ ہو تب ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے - ایمرجنسی اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب ملک کی سرحدوں کو خطرہ ہو یا ملک کے اندر کچھ غیر ملکی لوگ ملک کے رہنے والوں کی مدد سے افراتفری پھیلاتے ہیں - سازشیں کرتے ہوں، اور ملک کے رسل و رسائل اور خوراک کے پہنچانے کے انتظامات میں یا دوسری چیزوں کو جن کا شہری زندگی پر اثر پڑتا ہو روکنا بھی ایمرجنسی ہے - کچھ نہیں تو اس ماحول کو قائم رکھنا نہایت ضروری ہے - میں ان دوستوں کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا جو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی نہ ہو - چینی حملہ سے پہلے بھی اس ملک میں ایمرجنسی تھی اور چینی حملہ کے بعد تو ایمرجنسی کی بے حد ضرورت ہے -

رولز لاگو کئے گئے ہیں اور یہ اس لئے لاگو کئے گئے ہیں کہ ملک میں خوراک کی قیمتیں نہ بڑھیں اور ملک میں رسل و رسائل کو نقصان نہ پہنچے - اور ملک میں مذہب کے نام پر فسادات نہ کرائے جائیں -

श्री प्रकाश नारायन सप्रू : ये सब चीजें हो रही हैं ।

شری اے - ایم - طارق : یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن حکومت کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو روکنے کے لئے اس کو لاگو کیا گیا تھا ان کے روکنے میں اس کا صحیح حد تک استعمال نہیں کیا گیا ہے - اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں - ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بد قسمتی سے کئی ہزار سال پرانا ہے اور ہیک وقت ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں - ہمارا کلچر ایک شرافت کا ہے ، بزرگی کا ہے اور رواداری کا ہے اور تینوں چیزوں میں ہم مارے جاتے ہیں -

एक माननीय सदस्य : कौन कौन चीजें ?

شری اے - ایم - طارق : بزرگی، شرافت اور رواداری اور اس کی مثال میں خود کھڑا ہوں-تو ان تینوں چیزوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے - میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کے خیال سے آپ پچھلے دو مہینوں میں دیانت داری سے دیکھیں کہ کشمیر کے اندر کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس ملک میں ایمرجنسی کی ضرورت ہے - پاکستان کی سازشوں کے خلاف یا چین کی سازشوں کے خلاف ہی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس لئے بھی ایمرجنسی کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ مذہب کے نام پر ذات پات کے نام پر سوشلزم اور سرمایاداری کے نام پر اندرونی گڑ بڑ کرنا چاہتے ہیں اور گڑ بڑ ہوئی بھی ہے - جیسے بنگال میں ہوئی اور دلی میں اسٹرائکیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے کارخانوں میں اسٹرائکیں ہو رہی ہیں تو آج اس ملک کو اس وقت جنگی حالات کا سامنا ہے - ہماری سرحدوں پر ایک طرف ہماری فوجیں ہیں اور دوسری طرف چینی فوجیں ہیں اور ایک طرف ہماری فوجیں ہیں دوسری طرف پاکستانی فوجیں اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے - جس ملک میں جب اطمینان نہ ہو، جب سرحدوں کے رہنے والوں کو پورا یقین نہ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے تو ملک میں ایمرجنسی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے - ان چیزوں کو روکنے کے لئے یہ ڈیفنس آف انڈیا

دوسرے ملک کا حامی قرار دیا جائے اور اس ملک میں فساد ات کرائے جائیں اور ملک کے نظام کو خراب کیا جائے تو سوکار کا فرض ہے کہ ایسا کرنے والے لوگوں پر قانون استعمال کیا جائے -

اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک میں عام چیزیں جو دستیاب ہونی چاہئیں ان کے دام مہنگے ہو گئے ہیں اور اس پر ڈیفنس آف انڈیا رولز استعمال کرنا چاہیئے - دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہوا ہے جہاں ایمرجنسی کا اعلان ہوا - ایمرجنسی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو مخالف ہے ، جو اپوزیشن میں ہے اس پر اس کو استعمال کیا جائے - ڈیفنس آف انڈیا رولز کے معنی یہ ہیں کہ ملک کا اندرونی امن ہر قیمت پر قائم رکھا جائے - ڈیفنس آف انڈیا رولز کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو شخص سرکار کے خلاف نعرہ لگاتا ہے اس کو پکڑا جائے - ایمرجنسی کے معنی یہ ہیں کہ جو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے اور رعایا کو پریشان رکھے اس پر ڈیفنس آف انڈیا رولز کا اطلاق ہونا چاہئے - چاہے وہ قیمتوں کے بارے میں ، چاہے وہ اسٹرائکوں کے بارے میں ہو - چاہے وہ رسل و رسائل کو روکنے کے بارے میں ہو - یہاں ایک غلطی ضرور ہوئی ہے جو بعض دوستوں نے یہ کہا کہ ہم اس

[شری اے - ایم - طارق]

ظلم ہے اور جرم ہے کہ اس ملک میں رہنے والے کسی آدمی کو پاکستانی کہا جائے - میں سمجھتا ہوں مسٹر سپیرو اور آنریبل پانڈے میری اس بات میں حمایت کریںگے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ علی محمد طارق کو پاکستانی کہکر بد نام کیا جائے -

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : मैंने कभी नहीं कहा ।

شری اے - ایم - طارق : آپ کو میں نہیں کہتا ہوں - بہرحال کسی کی عزت کو اس کی جان و مال کو اور اس کے بچوں کو خطرہ میں ڈالنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی طرف خیال کرنا چاہئے - طارق کو نہ کہئے ہمایوں کبیر صاحب کو کہئے . . . .

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : उनको भी नहीं कहा ।

شری اے - ایم - طارق : کسی مسلمان کو اس ملک میں پاکستانی کہکر اس کی جان و مال کو خطرہ میں ڈالنا یہ بھی ایک خطرناک سازش ہے اور جو ایسا کرے اس کے خلاف ڈیفنس آف انڈیا رولز کو فوراً استعمال کرنا چاہیئے - صرف اس لئے کہ وہ اقلیت فرقہ کا ہے ، کرشچین ہے ، مسلمان ہے ، بدھ ہے یا سکھ ہے ، وہ اپنے سیاسی مقصد کے پیش نظر کسی

کہ ایمرجنسی نہیں مانتے ہیں کہ
وزیروں کے گھر میں شادی ہو تو اس
میں بجلی لگائی جائے - اگر کہیں
شادی ہوتی ہے تو ہم اس میں بجلی
بھی لگاتے ہیں اور پارٹی بھی دیتے
ہیں - ہم ایک بہت بڑے ملک کے
رہنے والے ہیں - انگریزوں کے زمانہ
میں بھی بال روم ڈانس ہوتے تھے اور
لوگ نائٹ کلب میں جاتے تھے -
ایک قوم کے معیار کو بلند رکھنے کے لئے
اور اپنے مارلس کو بلند کرنے کے لئے
انسان کو یہ سب کرنا پڑتا ہے اور میں
سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں
ہمیں کرنی چاہئیں - ورنہ ہم لوگوں
کو یہ معلوم ہوگا کہ شکست خوردہ
ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جو ہمیں
ملک میں پیدا کرنی نہیں ہے - ہمیں
اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم
بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور بالکل
چینیوں نے ہمیں کھا لیا ہے -

نہیں - بلکہ ہم نے اپنے لوگوں کے
دلوں میں ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ
ہم چینیوں کے، پاکستانیوں کے حملہ کا
مقابلہ کریں گے - نہرو صاحب نے
ابھی فرمایا ہے اور میں ان کی رائے کی
قدر کرتا ہوں کہ اگر ہمارا معاملہ چین
کے ساتھ پر امن طریقہ پر اور باعزت
طریقہ پر حل ہو جائے تو وہ کرنا
چاہئے - اگر پاکستان کے ساتھ بھی
با عزت طریقہ پر صلح ہو جائے تو ہم کو
صلح کرنا چاہئے اور یہ ہماری پالیسی

کے مطابق ہے لیکن جہاں ہماری عزت،
ہمارے ملک کی سالمیت پر اثر انداز
ہو تو ہمیں اسے کبھی نہیں ماننا
چاہئے وہ چین ہو ، پاکستان ہو، دنیا
ہو - کیوں کہ اگر ہم ویسا کریں گے تو
ہمارے ہندوستان کی شان اور ہندوستان
کی تاریخ کو بدلنا پڑتا ہے جو ہم
نہیں بدلیں گے - کیوں کہ ہم
ہندوستانی جانتے ہیں کہ ہمارے کلچر
میں وہ بات شامل - آج سے کئی
سو برس پہلے ہندوستان پر سکندراعظم
کے حملہ کے ؟ پورس کی شکست
ہوئی تھی تو اس نے پورس سے پوچھا -
میں "آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں ؟"
اور پورس نے کہا - " وہی جو ایک
بادشاہ کو بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہئے-"
یہ ہندوستان کے کلچر کا ایک صرف
نمونہ ہے - تو ہم دنیا کے لوگوں سے جو
بات چیت کریں گے وہ ایک آزاد ملک
کی حیثیت سے کریں گے - با عزت
قوم کی حیثیت سے کریں گے - ہم
وہ فیصلہ نہیں کرینگے جو ہمارے ملک
کی سالمیت، ہماری تاریخ اور ہمارے
حالات کے مطابق نہ ہو -

سرکار سے مجھے اس بارے میں دو
تین باتیں کہنی ہیں - ڈیفنس آف
انڈیا رولز کا اطلاق ایسے لوگوں پر بھی
ہونا چاہئے جو اخباروں کے ذریعہ،
کتابوں کے ذریعہ، تقریروں کے ذریعہ
اس ملک کی سالمیت کو خطرہ میں
ڈالتے ہیں اور اس میں کوئی رعایت

ایمرجنسی کے معنی یہ ہیں کہ جو ملکی حالات کے مخالف کام کرتے ہیں ان کے بارے میں قانون کو کبھی نہیں دیکھنا چاہئے کہ کرنے والا کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے - مذہب کیا ہے - اگر غلط کرتا ہے کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو قانون کے سامنے کھڑا کرنا چاہئے -

دوسری گذارش یہ ہے کہ جتنے غیر ملکی اخبار نویس اس ملک میں آتے ہیں ان کے خلاف بھی اگر ہم کو شکایتیں ملیں اور وہ شکایتیں ایسی ہوں جو ڈیفنس آف انڈیا کے تحت آتی ہیں تو ہم کو کم سے کم اس شخص کو چیک کرنا چاہئے - میں نے کل ہوم منسٹر صاحب کی خدمت میں ایک بات کی طرف جو ایک چھوٹی بات نہیں ہے بڑی بات ہے اس کی توجہ دلائی تھی - کشمیر میں جب گڑبڑ ہوئی اس سے نیویارک ٹائمز کے اسپیشل کارسپونڈنٹ کو کراچی سے فلائی کراکر دلی لایا گیا اور دلی سے کشمیر بھیجا گیا - جب کہ وہ کا یہاں دلی میں اپنا ایک کارسپونڈنٹ موجود ہے He is meant for India. He has to report what is happening in India. تو اس نے ایسی غلط باتیں لکھیں جیسا کہ اس نے یہ لکھا کہ وہاں کے مسلمان ہندوؤں کے خلاف ہیں - ہندو سامراج واد کے خلاف ہیں - ہندو حملہ آوروں کے خلاف ہیں - پھر

[شری اے - ایم - طارق]

نہیں ہونی چاہئے - جب ہم یہ تھوڑی سی رعایت کر دیتے ہیں پھر ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کس کو پکڑیں - اگر طارق کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر یا قاعدہ اس کا اطلاق ہونا چاہئے - اگر وہ ڈیفنس آف انڈیا رولز میں آتا ہے تو مقدمہ چلنا چاہئے لیکن اگر وزیر صاحب نے سمجھا طارق تو اپنا دوست ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کسی پر ہاتھ ڈالنا - ہمارے لئے یہ درست نہیں ہے یہ کہنا کہ ہمارے چند لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ ہندوستان کے دشمن ہیں - جیسا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، باجپئی صاحب مجھے امید ہے ناراض نہیں ہوں گے، ہر مسلمان جو اس ملک میں بستا ہے وہ ہندوستان کا دشمن نہیں ہے اور ہر ہندو جو اس ہندوستان میں رہتا ہے وہ اس ملک کا لائل نہیں ہے - کیوں کہ لائلٹی کسی قوم کی، کسی مذہب کی وراثت نہیں ہے لہذا ان باتوں کو سرکار کو دیکھنا چاہئے - اگر کانگریس پارٹی کے اندر کوئی شخص کسی قسم کی سیاسی یا سماجی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو قانون کے سامنے کھڑا کرنا چاہئے ورنہ ہم اٹل بہاری باجپئی کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھ سکتے - اور جس وقت ہم نے اس کو باندھ دیا اس وقت ہم جتنا میں غلط رائے پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو مخالفوں کو دبا رہے ہیں - تو

لیکن ہم جو مدد لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جس سے امداد لی ہے اس سے ہم نے غلامی پا لی ہے۔ (*Interruptions.*) پولیٹیکلی چھوڑئے . . .

(*Time bell rings.*)

ایک طرف ایسا ہوتا ہے کہ آسام کی سرحدوں پر بڑی گڑ بڑ ہے — ہندو و مسلمان کی گڑ بڑ ہے — پاکستان کی گڑ بڑ ہے — چین کی گڑ بڑ ہے لیکن کل کے ہی اخباروں میں تھا کہ ویسٹ جرمنی سے کچھ لوگ آرہے ہیں گارو ہلس میں ٹیلی ویژن کی فلم بنانے کے لئے — اب یہ سرکار کو دیکھنا چاہئے کہ جب ہماری سرحدوں پر اس وقت پاکستان کے ساتھ گڑ بڑ ہے، چین سے گڑ بڑ ہے رفیوجیز آرہے ہیں — جا رہے ہیں ایسے موقعہ پر ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن کیمرہ والے وہاں پہنچ جائیں گے — اب جب وہ فلم بن جائے گی اور ہندوستان کے باہر جائے گی تو پھر اٹل بہاری باجپئی، مسٹر طارق، باجی صاحب سب شور کریں گے اور سرکار کہہ گی ہمیں پتہ نہیں تھا — ان تمام چیزوں کا قنفلس آف انڈیا رولز کے ساتھ تعلق — جب ایمرجنسی ہے تو صرف میرے اور باجپئی صاحب کے لئے ہی نہیں ہے — ایمرجنسی باہر کے لوگوں کے لئے بھی ہے —

حال میں اسے غلط ہی نہیں — اگر یہ ان پارلیمنٹری نہ ہو — تو بہت بڑا جھوٹ کہتا ہوں — جب اس نے دیکھا تھا کہ اس جلوس میں ہندو، مسلمان، سکھ سبھی اکٹھے ہیں پھر بھی ایسی غلط باتیں کی — لیکن سرکار ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی ہے — اپنا تسپیچ بھیجنے کے بعد دوسرے دن وہ واپس کراچی چلا گیا — جب دلی میں نیویارک ٹائمز کا کارسپونڈنٹ بیٹھا ہے تو کراچی سے کارسپونڈنٹ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، تو سرکار کو ان چیزوں پر بھی نوٹس کرنی چاہئے — یہ سب چیزیں قنفلس آف انڈیا ایکٹ میں آتی ہیں — کیوں کہ ان تمام چیزوں سے ہندوستان کی شہرت کو خطرہ ہو سکتا ہے — کسی غیر ملک میں بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے پڑھا کہ کشمیر کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلاف ایجیٹیشن کیا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا — اور جہاں کہیں ہندو زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی جان و مال کو اور جہاں مسلمان زیادہ ہوں وہاں ہندو کی جان و مال کو خطرہ ہے — لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو نہ جانے امریکہ والے کیا کہیں گے — فوجی امداد کا کیا ہوگا — حالانکہ ہوگا وگا کچھ نہیں — آپ صدر ناصر کو دیکھئے اس نے روس، انگریز و امریکہ سبھی سے امداد لی لیکن اپنی ساری شرطیں بھی منوالیں

[شری اے - ایم - طارق]

جہاں آپ طے کرتے ہیں کہ اس ملک کے امن کو بگاڑنے کے لئے مسٹر باجپئی اور طارق ہی سازش کر سکتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہئے کہ باہر کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اس ملک میں سازش کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے :

THE DEPUTY CHAIRMAN: Fifteen minutes is the allotted time for discussion on Resolution. You wind up now.

شری اے - ایم - طارق : میں ختم کر رہا ہوں کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے : ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ ان میں مذہبی سیاسی اور سماجی ایکتا ہے - دوسری طرف کچھ لوگوں نے سازشیں کیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایک ایسی مصیبت میں آ گیا ہوں خود ذاتی طور پر کہ -

زاهد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا
اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

اٹل بہاری صاحب کہتے ہیں اس کا نام علی محمد طارق ہے - انور صاحب یہ سمجھتے ہیں اس کا نام علی رام ہے -

شری این - ایم - انور (مدراس) : خوامخواہ مجھے کیوں لاتے ہو - میں تو آپ کو کچھ نہیں سمجھتا -

شری اے - ایم - طارق : میں نے کہا اسی لحاظ سے آپ کا نام آ جائے - تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں کشمیر کی بات کرتا ہوں میں جانتا ہوں ہماری سرحدوں کے اندر گڑ بڑ ہوتی ہے اور بہت زوروں سے ہوتی ہے - کشمیر سے پاکستان میں آدمیوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں - ابھی ۲۰ آدمیوں کو لے گئے یعنی ایک بڑے ملک میں ۲۲ آدمی ۱۰ منٹ میں مار دیئے جائیں تو یہ ایمرجنسی نہیں تو کیا ہے - لیکن ایمرجینسی کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کاغذ پر آپ ایمرجنسی لکھیں - اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا جائز طور پر استعمال کریں ہم یہ معلوم کریں کہ ۲۲ آدمیوں کو جو اغوا کیا گیا ہے اس کے پیچھے سازش کیا ہے - ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایکسپلوزنس اور سمگلنگ کیسز ہو رہے ہیں - اب سرکار خود کہہ رہی ہے پاکستان ہمارے ہوائی جہازوں کو غلط راستہ بتاتا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں - یہاں بہت سے غیر ملکی ایجنٹ بیٹھے ہیں جو مقامی لوگوں سے مل کر ہمارے ڈیفنس کے موومنٹ سے واقفیت رکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا - تو ان چیزوں کو روکنے میں اس قانون کا استعمال بے حد ضروری ہے - اس قانون کا استعمال صرف مخالف جماعتوں کو

دبانے کے لئے نہیں ہونا چاہیئے - چاہے مسلم لیگ ہو، جن سنگھ ہو، اکالی ہو اس ملک میں جو اندرونی طور پر سازش کرتے ہیں ان کو دبانے کی بے حد ضرورت ہے - ان الفاظ کے ساتھ میں اس رزولیشن کی مخالفت کرتا ہوں لیکن پھر ایک دفعہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی کی پرزور حمایت کرتا ہوں -

†[**श्री ए० एम० तारिक** (जम्मू और काश्मीर) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, जहां तक इस रेज़ोल्युशन का ताल्लुक है मैं इसकी मुखालफत करता हूं ।

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : पूरी मुखालफत तो नहीं करेंगे ?

श्री ए० एम० तारिक : आधी करूंगा लेकिन जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है जितने नज़रबन्द हैं इस मुल्क में और काफी देर से हैं उनको छोड़ देना चाहिए अगर वो छोड़े नहीं जा सकते हैं तो उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं उनको अदालत में लाना चाहिये । इससे एक सूरत यह पैदा हो जायेगी कि मुल्क के जो चन्द लोग या चन्द जमायतें डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की मुखालफत सिर्फ इसलिए करती हैं कि इस मौजूदा सरकार ने उसे लागू किया है उनको लोगों में यह गलत बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स मौजूदा हुकुमत ने सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए लागू किए । बल्कि उनको यह यकीन हो जायेगा और हमें आवाम को भी यह बताना है कि डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स की जरूरत इस मुल्क में है, थी और आगे भी कुछ मुद्दत के लिये रहेगी । एमरजेंसी के माने ये नहीं हैं कि हमारे मुल्क में जंग हो तब एमरजेंसी पैदा होती है । एमरजेंसी उस वक्त भी पैदा होती है जब मुल्क की सरहदों को खतरा हो या मुल्क के अन्दर कुछ गैर मुल्की लोग मुल्क के रहने वालों की मदद से अफरा-तफरी फैलाते हैं, साजिशें करने में और मुल्क के रसद व रसायल और खूराक के पहुंचाने के इन्तजामात में या दूसरी चीजों को जिनका शहरी जिन्दगी पर असर पड़ता हो रोकना भी एमरजेंसी है । कुछ नहीं तो इस माहौल को कायम रखना निहायत जरूरी है । मैं उन दोस्तों के साथ इत्तफाक नहीं कर सकता जो यह कहते है कि मुल्क में एमरजेंसी न हो । चीनी हमले से पहले भी इस मुल्क में एमरजेंसी थी और चीनी हमले के बाद तो एमरजेंसी की बेहद जरूरत है । इस वक्त हमारे सामने कोई ऐसी जमानत नहीं है कि चीन और पाकिस्तान अलग अलग या मिल कर हमारी सरहदों पर हमला नहीं करेंगे । अगर आज हिन्दुस्तान को यह जमानत मिल जाय कि पाकिस्तान और चीन हिन्दुस्तान के इलाकों पर हमला नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान की सरहदों के अन्दर गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे तो एमरजेंसी बजाते खुद खत्म हो जायगी लेकिन इन दोनों चीजों की हमारे पास कोई जमानत नहीं है बल्कि अगर हम दयानत दारना और एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से यह छोड़ कर के कि हम किस जमायत के अन्दर हैं इस बात को देखें तो हमको यह यकीन हो जाता है कि इस मुल्क में एमरजेंसी है ।

मैं मि० भूपेश गुप्त की मुखालफत इस लिये नहीं कर रहा हूं कि वे मुखतलिफ जमायत के मैम्बर है या लीडर हैं और उन्होंने यह रेज़ोल्यूलशन पेश किया है बल्कि मैंने अक्सर मौकों पर उनकी हिमायत की है और मेरे दोस्त आनरेबल पांडे यह समझते हैं कि मै उनका ज्यादा साथी हूं और पाडे साहब का कम हूं लेकिन हकीकत यह है कि जब मुल्क

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री ए० एम तारिक़]

का मामला सामने हो तो उसमें अफराद की दोस्ती के माने कुछ नहीं रहते । मुल्क की अहमियत के ख्याल से आप पिछले दो महीनों में दयानतदारी से देखें कि काश्मीर के अन्दर कितने ऐसे केसिस हुए हैं तो आपको यकीन हो जायगा कि इस मुल्क में एमरजेंसी की जरूरत है । पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ या चीन की साजिशों के खिलाफ ही एमरजेंसी की जरूरत नहीं है बल्कि इसलिये भी एमरजेंसी की जरूरत है कि इस मुल्क में कुछ लोग मजहब के नाम पर, जात-पात के नाम पर, सोशलिज्म और सरमायादारी के नाम पर अन्दरूनी गड़बड़ करना चाहाते हैं और गड़बड़ हुई भी है । जैसे बंगाल में हुई और दिल्ली में स्ट्राइकें हो रही हैं, बड़े बड़े कारखानों में स्ट्राइकें हो रही हैं, तो आज इस मुल्क को इस वक्त जंगी हालात का सामना है । हमारी सरहदों पर एक तरफ हमारी फौजें हैं और दूसरी तरफ चीनी-फौजें हैं और एक तरफ हमारी फौजें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौजें और हालात ऐसे हैं कि कोई यह नहीं कह सकता है कि किस वक्त क्या हो जाय । जिस मुल्क में जब इतमीनान न हो, जब सरहदों के रहने वालों को पूरा यकीन न हो कि क्या हो सकता है तो मुल्क में एमरजेंसी खुद ही पैदा हो जाती है । इन चीजों को रोकने के लिये यह डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू किए गए हैं और यह इसलिये लागू किये गये हैं कि मुल्क में खुराक की कीमतें न बढ़ें और मुल्क में रुस्लो-रसायल को नुकसान न पहुंचे और मुल्क में मजहब के नाम पर फसादात न कराये जाये ।

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : यह सब चीजें हो रही हैं ।

श्री ए० एम० तारिक : यह सब चीजें हो रही हैं, इसमें मैं आपसे इत्तफ़ाक करता हू लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिन चीजों को रोकने के लिये इसको लागू किया गया था, उनके रोकने में इसका सही हद तक इस्तेमाल नहीं किया गया हैं । इसकी कई वजूहात हो सकती हैं । एक वजह यह है कि हमारा जो कल्चर है वो बदकिस्मती से कई हजार साल पुराना है और बयक वक्त हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं । हमारा कल्चर एक शराफत का हैं, बुजुर्गी का है और खादारी का है । और तीनों चीजों में हम मारे जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौन-कौन चीजें ?

श्री ए० एम० तारिक : बुजुर्गी, शराफत और खादारी और इसकी मिसाल मैं खुद खड़ा हूं । तो इन तीनों चीजों से हमें नुकसान होता है । मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा जुल्म है और जुर्म है कि इस मुल्क में रहने वाले किसी आदमी को पाकिस्तानी कहा जाय । मैं समझता हूं मि० सप्रू और आनरेबल पांडे मेरी इस बात में हिमायत करेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है कि अली मुहम्मद तारिक़ को पाकिस्तानी कह कर बद-नाम किया जाय ।

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री ए० एम० तारिक : आपको मैं नहीं कहता हूं । बहरहाल किसी की इज्जत को, उसकी जानोमाल को और उसके बच्चों को खतरे में डालना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी तरफ ख्याल करना चाहिये । तारिक़ को न कहिये, हुमायूं कबिर साहब को कहिये . . .

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : उनको भी नहीं कहा ।

श्री ए० एम० तारिक : किसी मुसलमान को इस मुल्क में पाकिस्तानी कह कर उसकी जानोमाल को खतरे में डालना यह भी ए

खतरनाक साजिश है और जो ऐसा करे उसके खिलाफ़ डिफेंस आफ इंडिया रूल्स को फौरन इस्तेमाल करना चाहिये । सिर्फ इस लिये कि वो अकलीयत फिरके का है, क्रिश्चिन है, मुसलमान है, बौद्ध है या सिख है, वो अपने सियासी मकसद के पेशेनजर किसी दूसरे मुल्क का हामी करार दिया जाये और इस मुल्क में फसादात कराये जायें और मुल्क के निज़ाम को खराब किया जाय तो सरकार का फर्ज़ है कि ऐसा करने वाले लोगों पर कानून का इस्तेमाल किया जाय ।

इसके साथ साथ हमको यह भी देखना है कि मुल्क में आम चीजें जो दस्तयाब होनी चाहिये उनके दाम मंहगे हो गए हैं और इस पर डिफेंस आफ इंडिया रूल्स इस्तेमाल करना चाहिये । दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसा हुआ है जहां एमरजेंसी का ऐलान हुआ । एमरजेंसी के माने यह नहीं हैं कि जो मुखालिफ है, जो अपोजीशन में है, उस पर इसको इस्तेमाल किया जाय । डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के माने ये हैं कि मुल्क का अन्दरूनी अमन हर कीमत पर कायम रखा जाये । डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के माने ये नहीं हैं कि जो शख्स सरकार के खिलाफ़ नारा लगाता है उसको पकड़ा जाय । एमरजेंसी के माने ये हैं कि जो एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करे और रियाया को परेशान रखे उस पर डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का इतलाक होना चाहिये, चाहे वो कीमतों के बारे में, चाहे वो स्ट्राइकों के बारे में हों, चाहे वो रस्लोरसायल को रोकने के बारे में हो । यहां एक गलती जरूर हुई है जो बाज दोस्तों ने यह कहा कि हम इसको एमरजेंसी नहीं मानते हैं कि वजीरों के घर में शादी हो तो इसमें बिजली लगाई जायें । अगर कहीं शादी होती है तो हम उसमें बिजली भी लगाते हैं और पार्टी भी देते हैं । हम एक बहुत बड़े मुल्क के रहने वाले हैं । अंग्रेजों के जमाने में भी बालरूम डान्स होते थे और लोग नाइट क्लब में जाते थे । एक कौम के मियार को बुलन्द रखने के लिये और अपने मोरल्स को बुलन्द करने के लिये इन्सान को यह सब करना पड़ता है । और मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीजें हमें करनी चाहिये । वरना हम लोगों को यह मालूम होगा कि शिकस्त खुरदा जेहनियत पैदा हो गई है जो हमें मुल्क में पैदा करनी नहीं हैं । हमें अपने लोगों को यह नहीं बताना है कि हम बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं और बिल्कुल चीनियों ने हमें खा लिया है ।

नहीं, बल्कि हमने अपने लोगों के दिलों में एक जज़बा पैदा करना है कि हम चीनियों के, पाकिस्तानियों के हमले का मुकाबिला करेंगे—सप्रू साहब ने अभी फरमाया है और मैं उनकी राय की कदर करता हूं कि अगर हमारा मामला चीन के साथ पुरअमन तरीका पर और बाइज्जत तरीका पर हल हो जाये तो फौरन करना चाहिए । अगर पाकिस्तान के साथ भी बाइज्जत तरीका पर तै हो जाये तो हमको तै करना चाहिए । और यह हमारी पौलिसी के मुताबिक है लेकिन जहां हमारी इज्जत, हमारे मुल्क की सालमियत पर असर अन्दाज हो तो हमें उसे कभी नहीं मानना चाहिये चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, दुनिया हो । क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो हमारे हिन्दुस्तान की शान और हिन्दुस्तान की तारीख़ को बदलना पड़ता है जो हम नहीं बदलेगें । क्योंकि हम हिन्दुस्तानी जानते हैं कि हमारे कल्चर में वो बात शामिल है । आजसे कई सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान पर सिकन्दरेआजम के हमले के आगे पोरस की शिकस्त हुई थी तो उसने पोरस से पूछा "मैं आपके साथ क्या सलूक करूं" । और पोरस ने कहा—"वही जो एक बादशाह को बादशाह के साथ करना चाहिए ।" यह हिन्दुस्तान के कल्चर का एक सिर्फ नमूना है । तो हम दुनिया के लोगों से जो बातचीत करेंगे वो एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से करेंगे, बाइज्जत शहरी की हैसियत से करेंगे । हम वो फैसला नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क की

[श्री ए० एम० तारिक]

सालमियत, हमारी तारीख़ और हमारे हालात के मुताबिक न हो ।

सरकार से मुझे इस बारे में दो तीन बातें कहनी हैं । डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का इत्तलाक एसे लोगों पर भी होना चाहिए जो अख़बारों के जरिए, किताबों के जरिए, तकरीरों के जरिए, इस मुल्क की सालमियत को खतरे में डालते हैं और इसमें कोई रिआयत नही होनी चाहिए । जब हम यह थोड़ी सी रिआयत कर देते हैं फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसको पकड़े । अगर तारिक़ कोई ग़लती करता है तो उस पर बाकायदा इसका इतलाक होना चाहिए । अगर वो डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में आता है तो मुकदमा चलना चाहिए लेकिन अगर वज़ीर साहब ने समझा तारिक़ तो अपना दोस्त है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जायेगा किसी पर हाथ डालना । हमारे लिए यह दुरुस्त नही है यह कहना कि हमारे चन्द लोग जो वहां बैठे हैं वो हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं । जैसा कि मैं आपको यकीन दिलाता हू बाजपेयी साहब मझे उम्मीद है नाराज़ नही होंगे हर मसलमान जो इस मुल्क में बसता है वो हिन्दुस्तान का दुश्मन नही है और हर हिन्दू जो इस हिन्दुस्तान में रहता है वो इस मुल्क का लायल नही है । क्योंकि लायलटी किसी कौम की, किसी मजहब की विरासत नही है, लिहाज़ा इन बातों को सरकार को देखना चाहिए । अगर कांग्रेस पार्टी के अन्दर कोई शख्स किसी किस्म की सियासी या समाजी गड़बड़ करता है तो उसको कानून के सामने खड़ा करना चाहिए वरना हम अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ-पांव नही बांध सकते और जिस वक्त हमने उसको बांध दिया उस वक्त हम जनता में ग़लत राय पैदा करते हैं कि यह तो मुखालिफों को दबा रहे हैं । तो एमरजेंसी के माने ये हैं कि जो मल्की हालात के मुखालिफ काम करते हैं उनके बारे में कानून को कभी नहीं देखना चाहिए कि करने वाला कौन है इसका अकीदा क्या है, मजहब क्या है । अगर गलत करता है, कोई भी करता है तो उसको कानून के सामने खड़ा करना चाहिए ।

दूसरी गुजारिश यह है कि जितने गैर-मल्की अख़बारनवीस इस मुल्क में आते हैं उनके खिलाफ भी अगर हमको शिकायतें मिलें और वो शिकायतें ऐसी हों जो डिफेंस आफ इंडिया के तहत आती हैं तो हमको कम से कम उस शख्स को वार्न करना चाहिए । मैंने कल होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक बात की तरफ जो एक छोटी बात नही है, बड़ी बात है उनकी तवज्जो दिलाई थी । काश्मीर में जब गड़बड़ हुई उस समय न्यूयार्क टाइम्स के स्पेशल कारसपांडेन्ट को कराची से फ्लाई करा कर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से काश्मीर भेजा गया । जबकि उनका यहां दिल्ली में अपना एक कारसपांडेट मौजूद है।

He is meant for India. He has to report what is heppening in India.

तो उसने ऐसी ग़लत बातें लिखी जैसा कि उसने यह लिखा कि वहां के मुसलमान हिन्दुओं के खिलाफ हैं, हिन्दू साम्राज्यवाद के खिलाफ है, हिन्दू हमलावरों के खिलाफ हैं । बहरहाल मैं इसे ग़लत ही नही—अगर यह अनपार्लिया-मेंटरी न हो तो—बहुत बड़ा झूठ कहता हूं । जब उसने देखा था कि इस जलूस में हिन्दू-मुसलमान-सिख सभी इकट्ठे हैं फिर भी ऐसी ग़लत ब्यानी की । लकिन सरकार उनके खिलाफ एक्शन नही लेती है । अपना डिसपैच भेजने के बाद दूसरे दिन वो वापिस कराची चला गया । जब दिल्ली में न्यूयार्क टाइम्स का कारसपांडेट बैठा है तो कराची से कारसपांडेंट को आने की क्या जरूरत है, तो सरकार को इन चीज़ों पर भी तवज्जा करनी चाहिये । यह सब चीजें डिफेंस आफ इंडिया एक्ट में आती हैं । क्योंकि इन तमाम चीजों से हिन्दुस्तान की शुहरत को खतरा हो सकता है । किसी गैर-मुल्क में बैठे हुए किसी साहब ने पढ़ा कि काश्मीर के मुसलमानों

ने हिन्दुओं के खिलाफ एजीटेशन किया है तो उसका क्या असर होगा और जहां कहीं हिन्दू ज्यादा हैं वहां मुसलमानों की जान व माल को और जहां मुसलमान ज्यादा हों वहां हिन्दू की जान व माल को खतरा है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो न जाने अमरीका वाले क्या कहेंगे। फौजी इमदाद का क्या होगा। हालांकि होगा-वोगा कुछ नही। आप सदर नासिर को देखिये, उसने रूस, अंग्रेज, अमरीका सभी से इमदाद ली लेकिन अपनी सारी शर्तें भी मनवा लीं लेकिन हम जो मदद लेते हैं तो सोचते हैं कि जिससे इमदाद ली है उससे हमने गुलामी पा ली है। (*Interruptions*) पोलिटीकली छोड़िये . . .

(***Time bell rings.***)

एक तरफ ऐसा होता है कि आसाम की सरहदों पर बड़ी गड़बड़ है। हिन्दू मुसलमान की गड़बड़ है, पाकिस्तान की गड़बड़ है, चीन की गड़बड़ है, लेकिन कल के ही अखबारों में था कि वैस्ट जर्मनी से कुछ लोग आ रहे हैं गारू हिल्स मे टेलिवीजन की फिल्म बनाने के लिये। अब ये सरकार को देखना चाहिये कि जब हमारी सरहदों पर इस वक्त पाकिस्तान के साथ गड़बड़ है, चीन से गड़बड़ है, रिफ्यूजीस आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे मौके पर एक ग़ैरमुल्की टेलिविज़न कैमरा वाले वहां पहुंच जायेंगे। अब जब वह फिल्म बन जायेगी और हिन्दुस्तान के बाहर जायेगी तो फिर अटल बिहारी बाजपेयी, मिस्टर तारिक, याजी साहिब सब शोर करेंगे और सरकार कहेगी हमें पता ही नहीं था। इन तमाम चीज़ों का डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के साथ ताल्लुक़ है, जब एमरजैन्सी है तो सिर्फ मेरे और वाजपेयी साहिब के लिये ही नहीं है, एमरजैन्सी बाहर के लोगों के लिये भी है। जहा आप तै करते हैं कि इस मुल्क के अमन को बिगाड़ने के लिये मिस्टर वाजपेयी और तारिक़ ही साज़िश कर सकते हैं, आपको देखना चाहिये कि बाहर के लोग भी कुछ ऐसे हैं जिन को इस मुल्क में साज़िश करने में बहुत बड़ा फायदा होता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Fifteen minutes is the allotted time for Resolutions. You wind up now.

श्री ए० एम० तारिक : मैं खत्म कर रहा हूं। काश्मीर मे जो कुछ हुआ है। एक तरफ अगर आप देखे तो काश्मीर के लोगों ने ये दिखाया है कि उनमे मजहबी, सियासी और समाजी एकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने साज़िशें कीं और बदकिस्मती ये है कि मैं एक ऐसी मुसीबत में आ गया हूं खुद ज़ाती तौर पर कि—

ज़ाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफ़िर जाना
और काफिर यह समझता है मुसलमान हूं मैं।

अटल बिहारी साहब कहते हैं कि इसका नाम अली मोहम्मद तारिक़ है। अनवर साहब यह समझते हैं इसका नाम अली राम है।

श्री एन० एम० अनवर : ख्वाहमख्वाह मुझे क्यों लाते हो। मैं तो आपको कुछ नही समझता।

श्री ए० एम० तारिक : मैंने कहा इसी लिहाज़ से आपका नाम आ जाये। तो मैं यह समझता हूं कि मैं जब काश्मीर कीबात करता हूं मैं जानता हूं हमारी सरहदों के अन्दर गडबड़ होती है और बहुत जोरों से होती है। काश्मीर से पाकिस्तान से आदमियों को खेंच कर ले जाते हैं। अभी २२ आदमियों को ले गये। यानी एक बड़े मुल्क में २२ आदमी १० मिनट मे मार दिये जायें तो यह एमरजेंसी नहीं तो क्या है। लेकिन एमरजेंसी के माने सिर्फ ये नही हैं कि कागज़ पर आप एमरजेंसी लिखें। इसके माने ये हैं कि इसका जायज़ तौर पर इस्तेमाल करें। हम यह मालूम करें कि २२ आदमियों को जो एम्बुश किया गया है इसके पीछे साज़िश क्या है। हमने इससे पहले कहा था कि एक्सप्लोसिव्स और

[श्री ए० एम० तारिक]

बंबिग केसिस हो रहे हैं । अब सरकार खुद कह रही है कि पाकिस्तान हमारे हवाई जहाजों को ग़लत रास्ता बताता है और भी बहुत सी बातें हैं । यहां बहुत से गैर-मुल्की एजेंट बैठे हैं जो मकामी लोगों से मिलकर हमारे डिफेंस के मूवमेंट से वाकफियत रखते हैं, इससे इन्कार नहीं हो सकता । तो इन चीजों को रोकने में इस कानून का इस्तेमाल बेहद जरूरी है । इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुखालिफ जमायतों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम लीग हो, जनसंघ हो, अकाली हो, इस मुल्क में जो अन्दरूनी तौर पर साजिश करते हैं उनको दबाने की बेहद जरूरत है । इन अल्फाज के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत करता हूं, लेकिन फिर एक दफा जो लोग पकड़े गये हैं उनकी रिहाई की पुरजोर हिमायत करता हूं ।]

شری ایں - ایم - انور : میڈم ڈپٹی چیرمین - مسٹر علی محمد طارق کی اردو تقریر کے بعد میں نے یکایک سوچا کہ میں مدراسی ہوں مگر مجھے بھی یہ خواہش ہے کہ اردو جیسی پیاری اور مشترکہ زبان میں جو وطن عزیز کی قومی یک جہتی کی شان ہے اسی زبان میں تقریر کروں - آپ جانتے ہیں کہ مدراس سے ہوں جو کشمیر سے کوئی دو ہزار میل دور جنوب میں ہے اور اردو سے میرا رشتہ وہی ہے جیسا کہ :

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں
تیرا نام رہے
کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ
رہے جام رہے

مجھے آپ محترم دوست مسٹر بھوپیش گپتا کی قابلیت کا بڑا احترام ہے اور ان کی انٹیگریٹی کے متعلق میں ہمیشہ یہی سمجھتا آیا ہوں کہ شاید ہی کوئی ان سے بہتر کمیونسٹ ہو - باوجود اس کے ایک بات ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے - ان کی تقریر کو میں نے بڑے غور سے سنا لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے —

یہ تقریر کا وقت نہیں یہ تدبیر
کا وقت ہے
یہ جوش کا وقت نہیں یہ
ہوش کا وقت ہے

ملک میں اب کیا حالت گذر رہی ہے- انہوں نے بہت سے اخباروں کا حوالہ دیا - کبھی "ٹائمز آف انڈیا" کے ایڈیٹوریل کا حوالہ دیا - کبھی "اسٹیٹسمین" کی طرف توجہ دلائی

We aae now sitting on the edge of a volcano.. لیکن یہ باتیں ماضی کی ہو چکی ہیں جو اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی باتیں تھیں - لیکن آج جس وقت ہم اس مارچ کے مہینہ میں اس ملک کی حالتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہم ایک کوہ آتش فشاں پر بیٹھے ہوئے ہیں - تو پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسٹر بھوپیش گپتا میں یہ جرات کیسے پیدا ہوئی کہ وہ یہ

نے جو جو باتیں یہاں پیش کیں میں سمجھتا ہوں کہ سہول لبرٹیز کے ہم علم بردار ہیں اور جمہوریت کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے ہمارے محترم بزرگ پی - این - سپرو کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سہول لبرٹیز کی جہاں تک ہو سکے ہم ضرورت سے زیادہ حفاظت کریں - شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں ایسا بہترین ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہو جیسا کہ ہمارے یہاں ۴۵ کروڑ اشخاص کر رہے ہیں - ہم نے مکمل آزادی دی ہے - ذرا غور سے آپ اخبارات کا مطالعہ فرمائے - خصوصاً وہ اخبار جو اپنی اپنی مقامی زبان میں شائع ہوتے ہیں - کبھی ہندی میں، کبھی اردو میں - کبھی غور فرمایا کہ کتنی ایسی اشتعال انگیز باتیں ان میں لکھی جاتی ہیں - کتنی فتنہ و فساد کی باتیں لکھی جاتی ہیں - کبھی کسی کے کیریکٹر کا اسیسینیشن ہوتا ہے، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ کچھ ہو - جب اپوزیشن والے اس قسم کی حکومت کی مداوت میں، حکومت کی مخالفت میں، ایسے ایسے جذبات ابھارتے ہیں جس سے فسادات ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تماشہ دیکھتی رہے - اور کوئی کارروائی ان پر نہ کرے -

کہیں کہ ہمیں ایمرجنسی کی اب کیا ضرورت ہے - ذرا ملاحظہ فرمائے ان کا ریزولیشن جس میں آپ کہتے ہیں -

"This House is of opinion that having regard to the improved situation in the country the state of emergency should now be ended."

آپ کے دماغ کو کیا ہوا ہے - انکو کس نے کہا کہ سچویشن ہماری امپروو ہو چکی ہے - میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاقل یا دانش مند اس صورت حال کو امپرومنٹ کہے گا - ساری دنیا جانتی ہے کہ قریب میں جو ملاقاتیں ہوئیں پریذیڈنٹ ایوب خاں کی اور مسٹر چو این لائی کی، ان ملاقاتوں کے بعد بھی ہمارے پاس یہ احساس نہیں کہ حالتیں ہمارے ملک کی بہت ہی بگڑتی جا رہی ہیں -

مجھے بہت ہی صدمہ ہو رہا ہے کہ میرے پیارے دوست مسٹر باجپئی، لیڈر جن سنگھ کو کیا ہوا - شاعر نے کہا خوب کہا :-

دل نادان تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے

وہ بھی اس خیال کے ہیں کہ ہمارے یہاں اس وقت ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے - مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ—حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا—انہوں

[شری این - ایم - انور]

میڈم ڈپٹی چیرمین - میں تو کہتا ہوں اور میرا دعوی ہے کہ حکومت نے برابر طور پر انتظامی کارروائی نہیں کی - کلکتہ کے حادثہ سے میں یہی کہونگا کہ ایسے اخبار جن کا رات دن یہی پیشہ ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کریں - ہر ایک کے ایمان پر، ہر ایک کی محبت پر ہر ایک کی وفاداری پر بد گمانی کی جائے - آخر اس فتنہ اور اس زہر کی حد کہا ہے - ہم آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں - میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں ہندوستان کے اس موجودہ نازک دور کا ذکر کرتا ہوں تو کبھی کبھی مجھ کو آتا ہے - کہ ہماری حالت آگے چل کر کیا سے کیا بدلے گی - جو حالت اس سال جنوری میں تھی وہ فروری میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی - اس مہینہ مارچ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مارچ مہینہ میں آفت اور بڑھے گی یا کم ہوگی - اگر کسی سے پوچھا جائے -- اور آپ جانتے ہیں کہ شہر کے امن و امان کے لئے ہر جگہ فائر بریگیڈ رکھے جاتے ہیں - فائر انجن کا ہونا ضروری ہے گو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر لمحہ کتنے فتنہ فساد ہوتے ہیں—کہیں آن کی آن میں آگ لگ جائے تب اس فائر انجن کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں - اگر ہم نے ایمرجنسی کو اسٹیچوٹ بک میں رکھدیا ہے تو اس سے ہم کو بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے اور قربانی کے بغیر ہم آزادی کو بحال نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں کسی انفرادی اور کسی پارٹی یا گروپ کی اہمیت نہیں ہے - جیسا کہ ہمارے محترم دوست طارق صاحب نے بڑی خوبی سے بیان فرمایا - یہ جو سوال ہے یہ ہمارے دیش کا سوال ہے، اس ملک کے امن و امان کا سوال ہے، ملک کی سلامتی کا سوال ہے - کیوں کہ آج ملک خطرہ میں ہے - چہلم ہے ہماری زندگی جب کہ یہ ملک آفت میں ہے - چاروں طرف سے آفت ہی آفت ہے - دنیا کی بہت سی طاقتیں مختلف طریقوں سے اس کے چاروں طرف جمع ہو رہی ہیں اور نہ جانے آگے چل کر ہندوستان کی عظیم الشان جمہوریت پر کیا حملہ ہونے والا ہے - بہت سی باتیں ہر جگہ سامنے آتے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو اخبار ہیں ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا دیش ہے اور ہندوستان کی مختلف قوموں کا اس قدر مل جل کر رہنا یہ بھی کسی کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے - ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اس موقعہ پر یہی سب سے بڑا تاریخی منظر پیش نظر ہو کہ ہندوستان میں مختلف قومیں اتنے اتفاق و اتحاد سے . . .

(Interruptions)

کل اور آج کی بات چھوڑئے - سیکولرزم یہ تو پندرہ سال کا پودا ہے - یہاں ہندو دھرم کی وجہ سے پانچ ہزار ورش سے مختلف قومیں ملتی جلتی آ رہی ہیں اور یہ ہمارا اسپرچول ہریٹیج ہے جو کہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے - یورپ میں بے شک عیسائی مذہب کے لوگ ہیں لیکن صرف ایک مذہب اور ایک کلچر کے ان کا لباس ایک ہے ، ان کی عادتیں ایک ہیں، ان کے کھانے پینے کا ڈھنگ ایک ہے بلکہ ان کا طرز زندگی سب ایک ہے لیکن زبان کا تقاضہ ہے کہ یوروپ میں، اتنی زبان کی دیواریں کھڑی ہیں پھلی اتنی قومیں ہیں کوئی جرمن ہیں ، کوئی فرنچ ہیں ، کوئی سوئس ہیں ، کوئی برٹش ، کوئی ڈچ ، کوئی فرینچ ہیں، کئی قومیں ہیں ، محض اس لئے کہ ان کی زبان کا تقاضہ ہے - باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں پندرہ سولہ زبانیں ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں ۱۰ یا ۱۲ قومیں ہیں ، باوجود اس کے کہ ہمارا طرز زندگی جنوب میں ایک طریقہ کا ہے اور شمال میں کئی طریقہ کا ہے - باوجود اس کے کہ ہمارے باہمی رسم و ریت، کھانا پینا، رہن سہن کہیں کہیں جدا ہیں ، باوجود ان تمام تفرقات کے ایک کرشمہ ہے ایک معجزہ ہے، یہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت چمنستان ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول ہیں -

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا -

ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا -

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا -

ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا -

یہ نمونہ دنیا کے کسی ملک نے پیش نہیں کیا - یورپ اور امریکہ کے لوگ جو ہمیں سبق دیتے ہیں سلامتی کا ، اتفاق کا، اتحاد کا، کیا ان کے ہاں اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے ؟ امریکہ میں گورے اور کالے لوگ جو مختصر تعداد میں ہیں لیکن اس قدر وہاں ریشیل کمپلیکس کے معاملہ ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ کنسٹی ٹیوشن میں حکومت نے مساوات کر رکھی ہے - ساوتھ افریقہ جس کی بد تمیزی کا دنیا کو علم ہے اب وہ ہمیں سبق دینے آیا ہے -

کعبہ کس منہ سے جاوگے غالب -

شرم تم کو مگر نہیں آتی -

یہ ہندوستانی ہیں جو ساری دنیا کو علم و ادب کا سبق دیتے آئے ہیں - یہ وہ ہندوستان ہے جس نے ساری دنیا کو امن و امان کا سبق دیا - یہ وہ ہندوستان ہے جو دنیا کو اتفاق و اتحاد کا نمونہ ہزار برس سے دیتا آ رہا ہے ، یہ کوئی پنڈت جواہرلال نہرو کا سبق نہیں ہے سیکولرزم

[شری این - ایم - انور]

کا ، یہ ایسا ماحول ہے جیسی ہماری سرزمین میں ہمارے آباو اجداد نے بحال رکھا - مبارک ہے - آفرین آفرین - آفرین -

سبق پڑھ پھر صداقت کا ،
شجاعت کا ، عدالت کا -
لیا جائیگا تجھ سے کام دنیا
کی امامت کا -

ایسے ایک سماج کو جب خطرہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے ، کہیں پاکستان سے ہے - کہیں چین سے ہے ، شاید دونوں سے ہے ، تو میں کہتا ہوں کہ ہوشیار رہنا چاہئیے - با ادب ، با ملاحظہ ، ہوشیار - یہ بات نہیں کہ ہم کمیونسٹوں کو یہ سمجھیں کہ ہمارے لوگ سب اس خیال کے ہو رہے ہیں - ان کی نیت کے بارے میں — مجھے معاف کیجئے ، مسٹر بھوپیش گپتا—مجھے یہاں اردو کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے —

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے
ڈوبینگے -

یہ مسٹر بھوپیش گپتا کی ذہنیت ہے کہ کمیونسٹوں کو گرفتار کرنے پر ہم کہیں آپ کو گرفتار نہ کر بیٹھیں - یہ تو مسئلہ مخالفین کا مفروضہ ہے - آج ہندوستان کی جو نازک پوزیشن ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے قانون کی ضرورت ہے - یہ نہیں کہ سول کموشن یا فرقہ وارانہ فسادات یہ ہم کو کبھی بھروسہ ہو سکتا ہے - اگر خدا نخواستہ کہیں سول کموشن ہو جائے تو اس کے بعد کیا فائر بریگیڈ آپ تلاش کریں گے ؟ آگ لگنے پر کوئی کنواں نہیں کھودتا ہے، اس کو پہلے سے تیار رکھئیے اور اسی لئے ایمرجنسی کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے -

کس کو خبر تھی کہ اس سال جنوری اور فروری کے مہینہ میں حضرت بل کا انسیڈینٹ ہوگا — میں ہمیشہ کشمیریوں کو مبارک باد دیتا ہوں جنہوں نے باوجود اشتعال انگیز ہنگاموں کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو ، سکھ ، بودھ ، عیسائی سب کے سب لوگوں نے بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ سیکولرزم کی آواز کو بلند کیا اور اسلام کی شان کو، اس کے بنیادی پیغام امن کو بحال رکھا اور کہیں فتنہ و فساد کے لئے موقعہ نہیں دیا — ہم کو بھی چاہئیے کہ اس ملک میں، اس بڑے دیش میں ، مختلف صوبہ جات میں، یہی نمونہ ہم بحال رکھیں — چاہے دشمنوں کی ہزار کوششیں کیوں نہ ہوں مگر اہل کشمیر کی طرح ہماری ایکتا میں فرق نہ آئے — ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کی نوعہ بھی ہو کہ ہمارے آپس

مگر میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ذرا ہندوستان کی فکر اپنے دل میں بیٹھا کر دیکھیں تو وہ جو سنتے ہوں گے اور جو مانتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہندوستان آج خطرہ میں پڑا ہے اور ہم سب کو یہ کہنا چاہیئے کہ اور بھی ہم قربانی کرنے کو تیار ہیں - آزادی کیا معنی رکھتی ہے - آزادی کیا خاک معنی رکھتی ہے جب یہ آزادی آہ و زاری کی صورت اختیار کرے - تو جب ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس آواز پر لبیک کہنا چاہیئے کہ اور بھی زیادہ طاقتیں گورنمنٹ کو دی جائیں تاکہ گورنمنٹ اس ملک کو دشمنوں سے نجات دلائے اور آپ ہم تہلکے دل سے سوچیں کہ یہ آزادی، یہ جمہوریت، یہ سیول لبرٹی کس طرح بحال رہے - یاد رہے کہ اتفاق میں طاقت ہے اور نہ میں ہلاکت ہے - اس لئے ایک رہو اور نیک رہو اور ایمرجینسی میں ملک کی حفاظت کے لئے دن رات ایک کر کے تیار رہو، خدا حامی و ناصر ہے -

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے-
مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی -

ہندوستان زندہ باد -

†[श्री एन० एम० अनवर : मैडम डिप्टी चेयरमैन, मि० अली मुहम्मद तारिक़ की उर्दू तकरीर के बाद मैं ने यकायक सोचा कि मैं मद्रासी हूं मगर मुझे भी यह ख्वाहिश है कि उर्दू जैसी प्यारी और मुश्तरका जबान में जो वतने अज़ीज़ की कौमी यकजेहती की शान है उसी जबान में तकरीर करूं। आप जानते हैं कि मद्रास से हूं जो काश्मीर से कोई दो

†[ ] Hindi transliteration.

میں فتنہ و فساد ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کی بھی بھی نیت ہو - میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب نردوش ہیں - ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہندو بھی ہوں، بہت سے ایسے مسلمان بھی ہوں، بہت سے ایسے بودھ بھی ہوں اور بہت سے ایسے عیسائی بھی ہوں جن کے دل میں ہندوستان کی محبت کا وہ جذبہ نہ ہو جو ہونا چاہئے - مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر ایک کو مذہب کی بنا پر وہم و گمان کا شکار بنایا جائے اور انسان انسان پر پل پڑے اور اپنے گھر کو آپ کمزور کرے - یاد رکھو -

خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر -
نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر -

یہ تو ایک طوفان بدتمیزی ہے - کیا یہی طریقہ ہے جس سے مسودہ بڑھے گی؟ یہ انسان کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کا کام ہے کہ فتنہ و فساد کو آگے بڑھاتے جائیں - اور کہیں ایسا نہ ہو :--

دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

"Give the dog a bad name and kill it". That is not going to meet the ends of the situation.

یہ شیطان کا راہ عمل ہے - مسٹر باجپئی اور مسٹر بھوپیش کہتا کی تقریروں کو سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ رائے ہے کہ ایمرجینسی نہ رہے - ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا—

[श्री एन० एम० अनवर]

हजार मील दूर जुनूब में है और उर्दू से मेरा रिश्ता वही है जैसा कि :

हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे,
कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे।

मुझे अपने मुहतरिम दोस्त मि० भूपेश गुप्त की काबलीयत का बड़ा एहतराम है और उनकी इन्टैगिरिटी के मुतल्लिक मैं हमेशा यही समझता आया हूं कि शायद ही कोई उनसे बेहतर कम्युनिस्ट हो । बावजूद इसके एक बात उनकी मुझे समझ में नहीं आ रही है । उनकी तकरीर को मैंने बड़े गौर से सुना लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि :

यह तकरीर का वक्त नहीं यह तदबीर का वक्त है,
यह जोश का वक्त नहीं यह होश का वक्त है ।

मुल्क में अब क्या हालत गुजर रही है । उन्होंने बहुत से अखबारों का हवाला दिया, कभी "टाइम्स आफ इंडिया" के एडीटोरियल का हवाला दिया, कभी "स्टेटसमैन" की तरफ तवज्जो दिलाई । "We are now sitting on the edge of a volcano. लेकिन ये बातें माजी की हो चुकी हैं जो अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर की बातें थीं । लेकिन आज जिस वक्त हम इस मार्च के महीने में इस मुल्क की हालतों पर नजर डालते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि गोया हम एक कोहे आतिश फिशां पर बैठे हुए हैं । तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मि० भूपेश गुप्ता में यह जुरअत कैसे पैदा हुई कि वो यह कहें कि हमें एमरजेंसी की अब क्या जरूरत है । जरा मुलाहिजा फरमाइये उनका रेजोल्यूशन जिसमें आप कहते हैं — This house is of opinion that having regard to the improved situation in the country the state of emergency should now be ended." आप के दिमाग को क्या हुआ है । उसको किसने कहा कि सिचुएशन हमारी इम्प्रूव हो चुकी है । मैं नहीं समझता कि कोई आकिल या दानिशमन्द इस सूरते हाल को इम्प्रूवमेन्ट कहेगा । सारी दुनियां जानती है कि करीब में जो मुलाकातें हुईं, प्रैजिडैंट अयूब खां की और मि० चाऊ-एन-लाई की, इन मुलाकातों के बाद भी हमारे पास यह एहसास नहीं कि हालतें हमारे मुल्क की बहुत ही बिगड़ती जा रही हैं।

मुझे बहुत ही सदमा हो रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त मि० वाजपेयी लीडर जनसंघ को क्या हुआ । शायर ने क्या खूब कहा—

दिले नादां तुझे हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है ?

वह भी इसी ख्याल के हैं कि हमारे यहां इस वक्त ऐमर्जेंसी की जरूरत नहीं है । मुझे बहुत ही दुख हो रहा है और हकीकत यह है कि—हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ । उन्होंने जो जो बातें यहां पेश कीं मैं मानता हूं कि सिविल लिब्रटीज के हम अलम-बरदार हैं और जम्हूरियत के अलम-बरदार होने की हैसियत से हमारे मोहतरिम बुजुर्ग पी० एन० सप्रू को मैं मुबारकबाद देता हूं कि सिविल लिब्रटीज की जहां तक हो सके हम जरूरत से ज्यादा हिफाजत करें । शायद ही दुनियां में कोई ऐसा मुल्क हो जहां ऐसा बेहतरीन एक्सपेरीमेंट किया जा रहा हो जम्हूरियत का जैसा कि हमारे यहां ४५ करोड़ अशख़ास कर रहे हैं । हमने मुकम्मिल आजादी दी है । जरा ग़ौर से आप अख़बारात का मुतालिया फरमाइए, खुसूसन वो अख़बार जो अपनी अपनी मकामी जबान में शाया होते हैं। कभी हिन्दी में, कभी उर्दू में। कभी गौर फरमाया कि कितनी ऐसी इश्तआल-अंगेज बातें उनमें लिखी जाती हैं, कितनी फितना व फसाद की बातें लिखी जाती हैं । कभी किसी के कैरैक्टर का एसेसीनेशन होता है चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो कुछ हो । जब अपोजीशन वाले इस किस्म की हुकूमत की अदावत में, हुकूमत की मुख़ा-

लफ़्त में ऐसे ऐसे जज़बात उभारते हैं जिससे फसादात होते हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि हुकूमत तमाशा देखती रहे और कोई कार्यवाही उन पर न करे।

मैडम डिप्टी चैयरमैन, मैं तो कहता हूं और मेरा तो दावा है कि हुकूमत ने बराबर तौर पर इनतज़ामी कार्यवाही नहीं की। कलकत्ता के हादिसा से मैं यही कहूंगा कि ऐसे अख़बार जिनका रात-दिन यही पेशा है कि मुख़तलिफ कौमों के दरम्यान फितना व फसाद पैदा करें, हर एक के ईमान पर, हर एक की मुहब्बत पर, हर एक की वफ़ादारी पर बदगुमानी की जाये। आखिर इस फितने और इस जहर की हद क्या है । हम आपसे दरयाफत करना चाहते हैं । मैं यह सोच रहा हूं कि जब मैं हिन्दुस्तान के इस मौजूदा नाज़ुक दौर का जिकर करता हूं तो कभी कलेजा मुंह को आता है कि हमारी हालत आगे चलकर क्या से क्या बदलेगी। जो हालत इस साल जनवरी में थी वो फरवरी में कहां से कहां तक बिगड़ गयी इस महीने मार्च को जब हम देखते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मार्च महीने में आफत और बढ़ेगी या कम होगी । अगर किसी से पूछा जाये— और आप जानते हैं कि शहर के अम्नो अमान के लिये हर जगह फायर ब्रिगेड रखे जाते हैं। फायर इंजन का होना जरूरी है गो उसके माने ये नहीं कि हर लम्हे कितने फितने फसाद होते हैं—कहीं आन की आन में आग लग जाए तब इस फायर इंजन की जरूरत होती है या नहीं ? अगर हमने एमरजेंसी को स्टेचूट बुक में रख दिया है तो इससे हमको बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है और कुर्बानी के बग़ैर हम आज़ादी को बहाल नहीं रख सकते हैं लेकिन यहां किसी इन्फ़ादी और किसी पार्टी या ग्रुप की अहमियत नहीं है । जैसा कि हमारे मुहतरिम दोस्त तारिक साहब ने बड़ी खूबी से ब्यान फरमाया, यह जो सवाल है यह हमारे देश का सवाल है, इस मुल्क के अम्नो अमान का सवाल है। मुल्क की सलामती का सवाल है । क्योंकि आज मुल्क खतरे में है । जहनुम है हमारी जिन्दगी जबकि यह मुल्क आफत में है, चारों तरफ से आफत ही आफत है । दुनिया की बहुत सी ताकतें मुखतलिफ तरीकों से इसके चारों तरफ जमा हो रही हैं और न जाने आगे चल कर हिन्दुस्तान की अजीमो-शान जम्हूरियत पर क्या हमला होने वाला है । बहुत सी बातें हर जगह सुनते आते हैं कि मुख़तलिफ मुमालक के जो अख़बार हैं उनमें यह लिखा जाता है कि हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है और हिन्दुस्तान की मुखतलिफ कौमों का इस कदर मिलजुल कर रहना यह भी किसी की आंखों में खटकता है । हो सकता है कि पाकिस्तान के इस मौके पर यही सबसे बड़ा तारीख़ी मंजर पेशे-नज़र हो कि हिन्दुस्तान में मुख़तलिफ कौमें, इतने इत्तफाक व इत्तहाद से... (*Interruption*) कल और आज की बात छोड़िए । सक्यूलरिज्म—यह तो पन्द्रह साल का पौधा है । यहां हिन्दू धर्म की वजह से पांच हजार वर्ष से मुख़तलिफ कौमें मिलती जुलती आ रही हैं और यह हमारा सिंपिर-चुअल हैरीटेज है जो कि दुनियां के लिए एक नमूना है । योरुप में बेशक ईसाई मज़हब के लोग हैं लेकिन सिर्फ एक मजहब और एक कल्चर के । उनका लिबास एक है, उनकी आदतें एक हैं, उनके खाने-पीने का ढंग एक है बल्कि उनकी तर्जे जिन्दगी सब एक है, लेकिन जबान का तकाजा है कि योरुप में इतनी जबान की दीवारें खड़ी हैं यानि इतनी कौमें हैं, कोई जर्मन हैं, कोई फ्रेंच हैं, कोई स्विस हैं, कोई ब्रिटिश, कोई डच्च, कोई स्वीड हैं, कई कौमें हैं, महज इसलिए कि उनकी जबान का तकाजा है । बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में १५–१६ जबानें हैं, बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में १० या १२ कौमें हैं, बावजूद इसक कि हमारा तर्जे जिन्दगी जनूब में एक तरीके का है और शमाल में कई तरीके का है, बावजूद इसके कि हमारे बाहमी रस्मो-रीत, खाना-पीना,

[श्री एन० एम० अनवर]

रहन-सहन, कही-कही जुदा है, बावजूद इन तमाम तफर्रकात के एक करिश्मा है, एक मुअजजा है, यह दुनिया के लिए एक नमूना है कि हिन्दुस्तान एक खूबसूरत चमनिस्तान है जिसमें रग रग के फूल हैं ।

सारे जहा से अच्छा हिन्दुस्ता हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा
मजहब नही सिखाता आपस मे बैर रखना
हिंदी हैं हम वतन है हिन्दुस्तां हमारा

यह नमूना दुनिया के किसी मुल्क ने पेश नही किया । योरप और अमरीका के लोग जो हमे सबक देते हैं सलामती का, इत्तफाक का, इत्तहाद का, क्या उनके यहा इस तरह के मसले नही होते ? अमरिका में गोरे और काले लोग जो मुख्तसिर तादाद में हैं लेकिन इस कदर वहां रेशियल कौम्पलैक्स के मामले होते हैं बावजूद इसके कि कान्स्टीट्यूशन में हकूमत ने मुसावात कर रखी है । साउथ अफ्रीका जिसकी बदतमीजी का दुनिया को इल्म है अब वो हमे सबक देने आया है—

काबा किस मुह से जाओगे गालिब
शर्म तुमको मगर नही आती ।।

यह हिन्दुस्तानी है जो सारी दुनिया को इल्मो-अदब का सबक देते आये है । यह वो हिन्दुस्तान है जिसने सारी दुनिया को अम्नो-अमान का सबक दिया । यह वो हिन्दुस्तान है जो दुनिया को इत्तफाक वा इत्तहाद का नमूना हजार वर्ष से देता आ रहा है । यह कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबक नही है सक्यूलरिज्म का, यह ऐसा महौल है जिसे हमारी सर जमीन में हमारे आबा-व-अजदाद ने बहाल रखा । मुबारक है आफरीन, आफरीन, आफरीन—

सबक पढ फिर सदाकत का,
शुजाअत का, अदालत का;
लिया जायेगा तुझ से काम,
दुनिया की इमामत का ।

ऐसे एक समाज को जब खतरा दोनों तरफ से हो रहा है, कही पाकिस्तान से है, कही चीन से है, शायद दोनों से है, तो मैं कहता हू कि होशियार रहना चाहिए । बाअदब, बामुलाहजा, होशियार । यह बात नही कि हम कम्यूनिस्टों को यह समझे कि हमारे लोग सब इस ख्याल के हो रहे हैं—उनकी नीयत के बारे में—मुझे मुआफ कीजिये—मि० भूपेश गुप्ता—मुझे यहां उर्दू का एक मिसरा याद आ रहा है—

हम तो डूबे हैं सनम तमको भी ले डूबेंगे ।

यह मि० भूपेश गुप्ता की जहनियत है कि कम्यूनिस्टों को गिरफ्तार करने पर हम कही आप को गिरफ्तार न कर बैठें । यह तो मसला मुखालफीन का मफूजा है । आज हिन्दुस्तान की जो नाजुक पोजीशन है उसकी अहमियत को देखते हुए इस तरह के कानून की जरूरत है । यह नही कि सिविल कमीशन या फिरकेवाराना फसादात पे हमको कभी भरोसा हो सकता है । अगर खुदा-न-खास्ता कहीं सिविल कमोशन हो जाए तो उसके बाद क्या फायर ब्रिगेड आप तलाश करेंगे ? आग लगने पर कोई कुआ नही खोदता है, उसको पहले से ही तैयार रखिये और इसलिए एमरजैंसी की हमको जरूरत पड़ती है ।

किसको खबर थी कि इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में हजरतबल का इसीडैंट होगा । मै हमेशा काश्मीरियों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने बावजूद इश्तआल अगेज हगामों के सिर्फ मसलमान ही नहीं बल्कि हिन्दु, सिख बौद्ध ईसाई सब के सब लोगों ने बडे इत्तफाक व इत्तहाद के साथ सैक्यूलरिज्म की आवाज को बलन्द किया और इस्लाम की शान को, उसके बुनियादी पैगाम अमन को बहाल रखा और कही फितना व फसाद के लिए मौका नहीं दिया । हमको भी चाहिये

कि इस मुल्क में, इस बड़े देश में, मुख्तलिफ सूबाजात में यही नमूना हम बहाल रखें चाहे दुश्मनों की हजार कोशिशें क्यों न हों मगर अहले काश्मीर की तरह हमारी एकता में फर्क न आए। हो सकता है कि दुश्मनों की नीयत यही हो कि हमारे आपस में फितना व फिसाद हों और यह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ लोगों की भी यही नीयत हो। मैं यह नहीं कहता कि हम सब निर्दोष हैं। हो सकता है कि बहुत से ऐसे हिन्दू भी हों, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हों, बहुत से ऐसे बौद्ध भी हों और बहुत से ऐसे ईसाई भी हों जिनके दिल में हिन्दुस्तान की मुहब्बत का वह जजबा न हो जो होना चाहिए। मगर इसके ये माने नहीं हैं कि हर एक को मजहब की बिना पर वहम व गुमान का शिकार बनाया जाये। और इन्सान इन्सान पर पिल पड़े और अपने घर को आप कमजोर करे। याद रखो—

खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर
न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर।

यह तो एक तूफाने-बदतमीजी है। क्या यही तरीका है जिससे मरव्वत बढ़ेगी। यह इन्सान का काम नहीं है बल्कि शैतान का काम है कि फितना व फसाद की आग बढ़ाते जायें और कहीं ऐसा न हो—

दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से
इस घर को आग लग गयी घर के चिराग से।

"Give the dog a bad name and kill it". That is not going to meet the ends of the situation.

यह शैतान का राहे अमल है। मि० वाजपेयी और मि० भूपेश गुप्ता की तकरीरों को सुनने के बाद मैं यह समझता हूं कि उनकी यह राय है कि एमरजेंसी न रहे—

यह वो लफ्ज कि शरमिन्दा-ए-मानी न हुआ—

मगर मैं कहता हूं कि वो अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें और जरा हिन्दुस्तान की फिक्र अपने दिल में बिठा कर देखें तो वो जो सुनते होंगे और जो मानते होंगे वो यह है कि हिन्दुस्तान आज खतरे में पड़ा है और हम सब का यह कहना चाहिए कि और भी हम कुर्बानी करने को तैयार हैं। आजादी क्या माने रखती है? आजादी क्या खाक माने रखती है जब यह आजादी आह्लाजारी की सूरत अख्तियार करे। तो जब हम दुश्मनों का मुकाबला करते हैं तो हमें इस आवाज पर लब्बेक कहना चाहिए कि और भी ज्यादा ताकतें गवर्नमेंट को दी जायें ताकि गवर्नमेंट इस मुल्क को दुश्मनों से निजात दिलाये और आप हम ठंडे दिल से सोचें कि यह आजादी, यह जम्हूरियत, यह सिविल लिबर्टी किस तरह बहाल रहे। याद रखें कि इत्तिफाक में ताकत है और नफाक में हलाकत है, इसलिए एक रहो और नेक रहो और एमरजेंसी में मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात एक करके तैयार रहो। खुदा हामी व नासिर है।

नशा पिला के गिराना तो सबको आता है
मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी।

हिन्दुस्तान जिन्दाबाद।]

SHRI KRISHAN DUTT (Jammu and Kashmir): Madam Deputy Chairman, I rise to oppose the Resolution sponsored by my hon. friend, Shri Bhupesh Gupta. I am really at a loss to understand how such a wide awake and experienced politician as Shri Bhupesh Gupta could sponsore such a Resolution at the present phase of Indian history. My feeling is that he has been motivated more by the anguish that he has felt at the arrest of his communist comrades. Instead of finding a remedy in some other direction for getting them released he has adopted a course of such a sweeping nature that it really cuts at the very roots of India's freedom and India's security. Instead of advising his friends to feel the gravity of the

[Shri Krishan Dutt]

situation obtaining in the country, asking them to fall in line with the other patriotic elements who are doing their best to strengthen the defence preparedness of the country, to strengthen the hands of the Government to meet any eventuality that the country may be called upon to meet at the borders, to give at this time an idea to people outside that there is now no reason left or that circumstances have so changed that the country does not need the state of emergency, is, I think, not doing any service to the country. No hon. Member, no patriotic Indian can say that the danger on the borders has lessened in any degree. On the contrary, keeping in view the reports in the press and the thickening relations between Mr. Ayub and Mr. Chou-en-lai, they are a pointer to a different conclusion. I feel that in the near future circumstances are going to shape themselves in a manner which will increase the danger to India. I am one with Mr. Anwar in feeling that the greatest discomfort and the greatest provocation which Pakistan is getting from India is our communal harmony, our secularism, our peaceful approach and our peaceful progress. This is not being tolerated at all by Pakistan. India is living in perpetual frustration of Pakistan's ideology or refutation of Pakistan's ideology. That is the greatest headache and the greatest frustration that Pakistan is feeling. Pakistani rulers are feeling in their hearts that unless and until India is also faced with some internal conflagration on the basis of a Hindu-Muslim conflict, the very basis or justification of Pakistan will disappear. If the present progress, communal harmony and peace continue in India, that is the worst condemnation of Pakistan that can be imagined Therefore, Pakistan wants that somehow or other India must be put in a position where it can justify the two-nation theory. Therefore, my reading is that Pakistan is going to manoeuvre events, is going to engineer events, which will create communal tension inside the country and will give added force to those elements which can work and which are even now working as a fifth column for Pakistan's aggression. Kashmir is not an end in itself for Pakistan. It is a means for the destruction of India's secular democracy. Pakistan wants to use Kashmir to enforce its domination on the whole of India. I think hon. Members will be surprised at what I say, but the ideology or the mentality of Kasim Rizvi is still in the minds of the rulers of Pakistan. The Muslim Leaguers have this basic idea in their mind that India's Government was taken over by the British from the Muslims and it is the Muslims who are entitled to rule Delhi after the withdrawal of the British. That is the idea which is ruling the minds of Pakistani rulers from the very start and inception of Pakistan. To keep up their theory there are persistent and constant efforts of the Pakistani rulers going on. Otherwise we cannot make out the motive behind the persistent refusal of the Ayub regime to the most natural and most sincere offer of our Government for a no-war declaration between India and Pakistan. What is behind their minds? Why don't they accept this straightforward offer? Why don't they wish that there should be eternal peace between India and Pakistan and inside India and inside Pakistan also? Therefore, connect this with that mentality of ruling Delhi just as Kasim Rizvi used to tell that he will just put the League flag on the Red Fort. That is the basic reason for Pakistan to continue its intransigence.

Now let me take the other side, China. Red China's rulers are militant Communists who want international Communist domination as far as possible on the surface of this earth—Communist imperialism of the Chinese variety, that is what I am referring to. By their massive invasion of 1962 they have grabbed more territory. They have strengthened their position all the more. They have got up-to-date roads, godowns and all

sorts of war arsenal and cantonments. Now they are in a very favourable position to advance further. Now add to this the most dishonest tactics which Mr. Chou-En-lai is practising, his collusion with Mr. Ayub Khan. This is a collusion between two aggressors. Both are now combining to grab as much of Indian territory by joint action as they can. Just as there are communalists who can be used as fifth columnists by the Pakistan rulers, there are also pro-Peking Communists here who can be used as agents for internal subversion against the Government of India and the Indian people to subvert our democracy, to subvert our freedom.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have always repudiated that charge and suggestion. Up till now they have not been proved.

SHRI KRISHAN DUTT: As a party you may have done it. That is quite correct. But I am talking of individuals.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have been in the last fourteen months asking Government to produce a shred of evidence against anybody. It is no question of resolution.

SHRI KRISHAN DUTT: That resolution also was not unanimous.

SHRI BHUPESH GUPTA: Why are you repeating a fourteen-month old allegation which is false, malicious and perverse?

SHRI KRISHAN DUTT: I have mentioned all this background with the sole object of stressing that the danger to Indian freedom and Indian integrity is increasing day by day. On the continuance of the emergency there can be no two opinions. With regard to the arrests and the misuse of the powers under the Defence of India Rules, that is a separate question altogether. The right use or the wrong use of the powers is not a determining factor either for the revocation or the retention of the emergency. The real factor that determines the fate of this resolution is the intensity of the state of danger in which we are at present placed with regard to our neighbours, north, east and west. I hope and I am confident that the hon. Members here and even the people outside are fully conversant with the seriousness of the situation in which our country . present is.

I may again refer to the example of the fire brigade used by my hon. friend Mr. Anwar. At present there is no actual firing going on on the borders. That is quite correct. But should we have the fire brigade only when the conflagration is on and the flames are shooting to the skies? The flames may have been quenched but the smouldering fire would be still there, and we cannot tell the fire brigade to pack up and go away just because the flames have been quenched. But when the smouldering fire is still there, we must keep the fire brigade on the spot till it is totally extinguished.

SHRI BHUPESH GUPTA: You keep the fire brigade in the depot.

SHRI KRISHAN DUTT: Not in the depot. Fires are smouldering on the border.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not asking you to demolish the fire brigade. Keep it in the depot. Likewise keep the emergency in the Constitution.

SHRI KRISHAN DUTT: It must be kept in action. Now the greatest task before the country at the present moment is preparing for defence, and not only for defence, we have to take back the territory from the Chinese illegal occupation. We are pledged to that. There is a sacred resolution of this hon. House on that point, and the time is fast coming when India will be compelled by the intransigence of the Chinese to take positive action there. For that positive action we

[Shri Krishan Dutt]
are going to prepare and prepare most valiantly and determinedly Thank you

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय उपसभापति महोदया, मैं श्री भूपेश गुप्त के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खडा हुआ हू । जो इलीले श्री भूपेश गुप्त ने दी हैं वे गलत है और कोई भी उनसे सतुष्ट नहीं है । एक तो आपने यह कहा कि चीन वापस चला गया है, मोज फायर लाइन कान्सालिडेट हो चुका है और अब कोई खतरा नहीं है । लेकिन खतरे को कम समझना, यह बिल्कुल ही गलत बात होगी । चीनी लोग जहा थे वहा और ज्यादा मजबूती से गडे हुए है । वे जमे हुए हैं और उन्होंने अपनी फौजें और ज्यादा कर दी है, हथियार बढा लिये है, बहुत से हवाई अड्डे वगैरह बनाए हैं । तो वे पूरी तरह से अपनी जगह पर हैं और ज्यादा मजबूती से जमे हुए है ।

फिर इसके अलावा पाकिस्तान भी इन दिनो हिन्दुस्तान के खिलाफ हो रहा है और जगह जगह ऐसी घटनाए होती है कि वह हमारे मुल्क मे आकर हमारे सिपाहियो को मार जाते है, हमला कर जाते हैं और दूसरी तरह से उनकी तैयारियां है । पाकिस्तान और चीन की फौजे भी हमारी सीमा पर बराबर लगी है । इसका मतलब यह है कि खतरा कम नहीं है बल्कि खतरा ज्यादा है । दूसरे, इस बात को मान लेना कि खतरा कम हो गया है, चीन का मोज फायर एक तरह से कान्सालिडेट हो गया है, हम इस खतरे को, हमले को हल्का समझते है, या एक तरह से अगर हम चीन की सद्भावना समझ कर विश्वास कर लेते हैं तो एक बहुत गलत दलील को मान लेते हैं । दूसरे विरोधी पार्टी के एक सदस्य श्री वाजपेयी जी ने इस दृष्टि से कहा कि मैं यह नहीं कहता कि खतरा कम हो गया है हमले को मैं हल्का नहीं समझता हू लेकिन पावर्स का मिसयूज हुआ है, दफ्तरो ने कुछ गलतिया की है और फिजूलखर्ची हुई है, इसलिए मैं इस विवाद का स्वागत करता हू ऐसा श्री वाजपेयी जी का कहना है । उनकी यह दलील भी कि किसी अफसर ने गलती की हो या किसी अफसर ने इस कानून का दुरुपयोग किया है, मै इस दलील को भी नहीं मानता हू । जब देश को और ज्यादा खतरे का सामना करना है तो ऐसे समय मे जो देश के पास सब से बडा हथियार कानून का है उसे हमे रद्द नहीं करना चाहिये । हमे यह नहीं समझना चाहिये कि गवर्नमेंट के किसी अफसर ने, गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने या किसी राजदूत ने कहीं कोई गलती की हो तो हमे इस हथियार को छोड देना चाहिये । असल मे जब देश मे एमरजेंसी है तो हमे सबको ज्यादा काम करना चाहिए । एक दलील यह भी दी गई है कि सीमा से १०० मील तक इस एमरजेंसी को लागू किया जाय और बाकी देश से इसको हटा लिया जाय । इसके सबध मे मैं यह कहना चाहता हू कि यह एक अव्यवहारिक बात है । इस समय सारे देश मे एमरजेंसी रखना चाहिए और सब पार्टियो को देश की हिफाजत मे गवर्नमेंट का साथ देना चाहिये । हर पार्टी को अपनी अलग अलग खिचडी नहीं पकानी चाहिय ।

अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री नन्दाजी ने अपने भाषण मे बतलाया कि एमरजेंसी का बहुत व्यापक रूप मे इस्तेमाल नहीं किया गया है और बहुत ही कम मामलो मे इसका इस्तेमाल किया गया है और न कानून का दुरुपयोग ही हुआ है । उन्होंने आकडे दे कर बताया कि बहुत ही कम कम्युनिस्टो को गिरफ्तार किया गया । लेकिन कुछ दूसरे लोगो को, मसलन कुछ व्यापारी है, कुछ अन्य लोग है जिन्होंने गलत काम किये है उन्हें गिरफ्तार किया गया है । इसलिए श्री भूपेश गुप्त जो यह कहते हैं कि एमरजेंसी को हटा देना चाहिये वह यह बात सिर्फ अपने

कुछ साथियों को लड़वाने के लिए कहते हैं । अगर इस बड़े हथियार को वे सरकार से हटवाना चाहते है तो इससे देश का बहुत नुक्सान हो जायेगा । मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ यही कहूंगा हमारे देश की इस समय जो हालत है उसको देखते हुये यही कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश के ऊपर खतरा बढ़ गया है । इस कानून का मिसयूज होने और कुछ गलतियों के बारे में जो बात कही गई है उससे यह साबित नहीं होता है कि देश की ऐसी परिस्थिति हो गई है जिससे हम इमरजेंसी को हटा दें । इसलिए इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi) Madam Deputy Chairman, I rise to oppose the Resolution of Mr. Bhupesh Gupta seeking that the emergency may be ended. I think the danger to the country which started with the invasion of the Chinese of this country has not ended. The threat from Pakistan to India has not ended As a matter of fact, all through this period, for more than one or one and a half years, on various occasions and at various times, there was much fear and anxiety that some attack might come from China during the winter period or that some trouble might take place on the Pakistan border, and those fears were there almost constantly all through this period Therefore, there is no occasion to feel that the emergency could be ended or to feel that there was no danger to the country's security or that there is no internal danger or external danger The emergency was declared and the country become mobilised for preparation and work to meet the aggression But there have been various factors and trends which have not been very happy Government declared the emergency which was very, very necessary, it had to declare an emergency Even before it was declared, the moment the Chinese aggression came I felt that a state of emergency should be declared, and a few days after that, it was declared Now the trouble from them continues

Personally I would say that the Government has not taken as strong an action against the various people, the various elements and the various trends as they should have done to meet the situation If it is an emergency, then it means that we should prepare the country for defence and make other preparations, not in the next 20 years but in the next three years we should complete the entire programme of defence and other preparations, we should not spread it over so many years as could be done normally or even as it is done today I am very radical in this, and I do feel that to take this work easy and to go slow about it is not going to help the situation I fully appreciate that the Government is doing its utmost to make the various preparations to increase production, to increase the number of the fighting forces in the various units and so on and much work is being done, much of which is personally known to me also. All this work is being done and I do appreciate that the Government is doing everything to increase our preparedness, military preparedness and so on But I must say that even that does not seem to go far enough, that is not enough as far as our preparations and our handling of the present situation are concerned It is important to quicken the pace even further I could quote even a large number of examples here to show that the Government machinery does not seem to function as fast and as promoptly as it should There may be—and I am sure that there are—many Ministers working very hard, overworking, hardworking, with serious concern and deeply distressed over the state of affairs and anxious to meet the state of affairs There seem to be quite a few officers also who are anxious and worried and who work very hard But apart from these very small sections of people—that means the large number of Ministers and a few officials—it seems to me that by and

[Kumari Shanta Vasisht.]

large, the bureaucratic machinery could not care less as to what is happening in the country. This is my impression from the various offices, from various people.

And another factor is that we are very little conscious of the military preparations, as to how they are or they should be. Whenever the question comes up that the military authorities should be given the necessary sanction, it takes months and months. Nobody bothers to give these sanctions. That applies to the various departments and the Ministries. When the land is wanted by the Cantonment Board, every single member of the Board seems to be so unconcerned and so indifferent as to feel why the Board, the Contonment Board, should want some more land for the antonment area. We have no desire to give land to the Cantonment Board whereas we are very anxious to give land for a cinema house or for a luxury hotel because the Tourist Department wants it. It is more concerned about the tourists, half the number of whom may come for intelligence work. The officials do not seem to have half as much concern for their own country's preparations. These are the examples with which even I personally come in contact. Those very members of the Boards and the Committees are more anxious to have hotels and cinemas and shopping areas and commercial areas and increase the prices of land by declaring it to be a commercial area or an industrial area, etc. But there is no consciousness, there is no feeling, there is no understanding that military areas are more important, that military facilities should be given to them or that these are more important than all these cinema houses and hotels. In the Master Plan various parts are marked as defence area; all those have been beautifully marked in the Master Plan of Delhi, and every single patch which is supposed to be used by the Defence Department or by the military authorities is marked there. And the Master Plan is sent to America so that they can appreciate what a beautiful Master Plan we have prepared. Whether we will implement it or not is another matter. But that Plan with all the marking, etc. is given out to them because we have no concern at all that many things in this country must be kept secret. Our planning must not become public property. The defence preparation of India is not meant for exhibition and publication abroad. But our planners, in their great joy and enthusiasm, our Government officials also in great pride and enthusiasm, feel that we must have a good certificate from the American planners. They do not realise that the country must function whether the American planners give them a certificate or not. That is not necessary. All your military areas or defence areas, here or anywhere else, whatever installations you have there, these are well known to everybody else. Here I would point out that when we had this emergency—and it is there—we have allowed so many foreign people, so many foreign correspondents and foreign people to go to every part of our country. They can go to the border areas; they can go to the trouble spots. Every single trouble spot in India, in the last few years, has been visited by a large number of foreign people; whether we can go there or not does not matter; whether we are given any facilities to see our areas, is not necessary. But every other foreigner, who wants to go into any part of India, and particularly the trouble spots on our borders, they are given all facilities and all sorts of help to go there which, I think, should never be allowed. The British people would never allow anybody to go to their own trouble spots. The Americans would never allow such a thing. The Russians would never allow such a thing. The Chinese would never allow such a thing. But we are casual and careless about our own state of affairs, and we think that India is the property of the whole world and we are their children to be patted by everybody in the world, and we do not bother that we should keep the

secrets of the Government, we should keep our military secrets, we should think of the security of the country. The foreigners come and they take photographs of all your Himalayan areas, through the plains and otherwise, and we do not bother to see that nobody should take photographs of all this terrain or that area, as if these were small matters.

Then sanctions are not generally given; I do not think the Defence Ministry, in its decency or good sense, or even its own self-respect, would publicise the fact that sanctions are not available to them. How can they say it? They would not say it; it would not help them very much either. But it is the responsibility of all the other Ministries, and the Government as such, to see that every little demand made by them, every single sanction asked for by them, should be promptly dealt with, within twenty-four hours. I am even aware that the wagons of the railways are not made available for military work. What are the wagons for? Why can't they be available for military purposes, and why can't they be given the priority? And these military preparations and defence preparations should be their very first priority and the decisions should be taken, all decisions, at least a large number of decisions, should be taken within twenty-four hours or within two days. But they sit over the files for months and months and months. Nobody bothers about the decisions, and so on. Of course some Ministers, I am sure, must be sleepless, worrying about the country. But, by and large, the bureaucracy and the machinery do not care, and this is not the way to tackle serious problems of the country. I would more concretely say; though we have not had trouble directly with Pakistan so far, and China did not come back after they providentially went back, supposing there is an attack this spring, supposing there is an attack this summer, am I to understand that the Government is ready for it? I am sure they are not ready, and I am very sorry to say this. I understand their limitations, but the fact remains that the machinery goes very slow and that they are not at all ready to face a situation of this kind. Of course, if that attack comes, everybody will become active all over again and the machinery will start going—no doubt there will be panic and fear—and again mobilisation of all our resources to meet the situation. But knowing full well that there are as many chances of an attack coming as there are of its not coming, we have not made the full preparations that were absolutely necessary. Another point I would say—which even in connection with the debate on the President's Address I had pointed out—that full co-operation must be given to the Defence Department and the Defence Ministry for their work, that work should be expedited and the requirement quickly tackled. I do not know how far the Government was bothered about it, but I hope they will do something.

Another thing is that prices have been rising tremendously. Though we have the Defence of India Rules and all sorts of other Rules in this emergency, prices have gone up like this, and the Government has not been able to check it. I am very happy to say that the Finance Minister has presented a very good, a very nice Budget; he has also felt it and is concerned about the rising prices. We are merely saying we are concerned and we are concerned and we will try not to let the prices go up, whereas they are going up all the time. By merely saying that you do not want the prices to go up, the high prices now are not going to remain under any sort of check. Prices are going up, much to the dislike and resentment of the people at large. By and large the entire country feels the impact of these prices; they resent it and feel bad about it. But the Government has remained, unfortunately, somewhat indifferent and callous in this matter. They say they are concerned, but I have never seen them take any effective steps to check the rising prices. Perhaps the influence of the trading community or the business community

[Kumari Shanta Vasisht.]

is so much on them that they do not know what to do, whom they should displease and whom they should not displease. And if they touch one section, that section will try to hit at those people as there are lots of man-eaters at large, and if they try to irritate some vested interests or the other, I fully appreciate and understand that these people will get into trouble. The Ministry also will find various obstacles and troubles and pin-pricks. I sympathise with them in their predicament, which is their predicament as well as our predicament. But this situation has to be faced whether you like it or not, these rising prices have to be tackled. The resources may be taken over, the distribution may be taken over. How is it that the producer gets nothing whereas the distributors are practically making hundred per cent profit even in foodgrains, and a shortage is created? And all this is happening, but the Government is not particularly taking any strong action. By saying: "We shall take action; we shall take action", they will go on for, say, five years. And so when shall you take action? But if no action is taken now, this problem will remain and it will recoil on the Government, so that action is necessary to meet the situation as it is today. Even in the interests of the Government and in the interests of the business community, in the interests of the business people, it is necessary to ease the situation, so that the various sections of the people can live in peace and be able to manage their livelihood somehow. Otherwise, these elements who are hard hit, will rise in revolt against the well-to-do in the society, against the moneyed people of our country, against the business people here, against the government itself, they will feel a tremendous amount of resentment, and the resentment and various other things will recoil, and that will be against the interests of the Government as well as the business people and the moneyed people. Therefore, in the interests of all these sections it is important to see that the prices do not rise—no matter what steps the Government have to take.

Lastly I would again say one thing more displeasing. I am in the habit of displeasing various people, Ministers and various sections of people. (*Interruptions*) But I hope they will appreciate what I am saying. Now I wish to say a word about the press. The press has also behaved sometimes nicely and sometimes very badly. When the trouble was on, that is, the Chinese attack came, then they were co-operative, very helpful, and by and large the Government got very good co-operation while the trouble was going on. But after that there are large numbers of weeklies, and daily papers, and yellow press and much rubbish is thrown before the people—fed to the people—speaking against everybody, beginning from the Prime Minister, doing every type of damage that they could do, to the Government, to the various Ministries, to the Prime Minister, to the Congress Party, to our programmes, to our Plans, and everything. A whole spate of materials is out, most irresponsible, some of which are using their blackmailing and bullying tactics. But the Government has not bothered to take any action against them. If this type of emergency was faced by any other country, they would have banned at least half a dozen papers they would have taught a lesson to the others . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is time.

KUMARI SHANTA VASISHT: . . . and no papers would have misbehaved as our papers sometimes seem to misbehave, and they do not spare anybody under the sun. It is God probably who is left out by them. And the press has sometimes behaved in a very partisan spirit, with very great vengeance, with an axe to grind, with selfish interests and motives, and with very great unfairness—if I may say so. Press is the fifth estate; they are supposed to have a certain amount of responsibility, a certain kind of responsibility. We were hoping that they would behave with responsibility. But

if the press people do not behave, it is for the Government to see to it, to take them to task, to ban those papers, not allow that much of pernicious propaganda to be carried on against the Government as well as against the Ministers and against the Congress Party itself, and for the last so many years, two years or three years or even more, every day, there is a cartoon with a Gandhi cap Today you are ridiculing the Gandhi cap Some time, even these papers may have cause to regret what they are writing today, all the caricatures they are making, all the cartoons they are putting out If any research scholar wants to sit down and study political situation today and make a collection, even for the study of political history only of these cartoons, he will make out the picture of the rot that is reflected in these papers today, a rot that is reflected in the indifference of the Government, and the indifference of all of us when we see our Gandhi cap being ridiculed day after day after day, for years and years and years, and we are indifferent, we do not bother At best you may criticise an action, you may criticise a programme or a policy or even certain individuals But this Gandhi cap is being ridiculed for months and years, and the Government is not bothered Why should these papers be allowed to ridicule the Gandhi cap? After all, these were the relations of the editors of these very papers who were responsible for these caps as well as the Congress movement, the freedom movement, and they are today indifferent to the work done by their fathers and grand fathers, and they are now bringing a bad name to the Party, to the Government, to the Ministers, to even the great leaders of our country, who are great leaders not only in this country but in the entire world, who are respected But our own people, very small people, ridicule our leaders They make fun of them They ridicule our Gandhi cap They ridicule our Ministers They show some Ministers sleeping, some Ministers doing something else They show as if our Ministers do not understand what is going on in the House and they do not know what they are speaking If they do not know what to speak, how would they be here? They say everything they possibly can Even a student doing some research would make out a sad picture of these papers They condemn our own Government by saying very fantastic, crazy, highly mischievous things I think it should be for the Government to put an end to this sort of mischievous behaviour of these papers Let me say that these papers will some day regret what they have been doing because they undermine *the national interests* Naturally from the trends in the press I feel there is a mischievous propaganda going on all over against the Government in order to undermine it and the Government does not seem to bother about it When all this trouble accumulates and the cumulative effect of it is felt after five or ten years, at that stage we will not be able to mend matters Today these matters can be mended They should be examined by the Government and something done about it before it is too late when we shall be only feeling sorry and shedding tears That, then, would not be the time for us to put any corrective to these things So today when we see these trends, when we see all these things, let us take action about it Let us go about it in the spirit of the emergency that is there and show that we mean to tackle the task.

Thank you

SHRI BHUPESH GUPTA Madam Deputy Chairman, it is good that this subject has been discussed It is not possible for me within the time at my disposal to answer every single point which has been sought to be made out by the Members opposite The hon Members opposite were, were, between themselves, sharing the orchestra played by the Home Minister The music came but the tune was set by him He played it He set the tune as to whether the emergency should remain or not I cannot expect, naturally the hon Members of the Congress Party to

[Shri Bhupesh Gupta.]

support me openly. But some of them indirectly have done so. Perhaps they are not conscious of the extent to which they have done so. But none the less they have done so.

I am very grateful to the hon. Members, Mr. Vajpayee, our friend, Mr. Dahyabhai Patel, and others who have supported this resolution—Mr. Gaure Murahari, Mr. Kureel and others including Mr. Mani. I counted 14 names of the hon. Members who have clearly supported the demand for ending the emergency.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: With reservation.

SHRI BHUPESH GUPTA: But you have not supported it, I know that. If I had taken free votes, I would have got this thing passed. It is quite clear. Now let me deal with the arguments. But I should like to concentrate on the arguments given by the Home Minister and by the Prime Minister. First of all, I would like to say that listening to the speeches I felt that we were facing something which I had never known. These speeches would stand in sharn contrast to what was said in November, 1962 when the Proclamation was being discussed in this House and the Home Minister spoke. If you read the speech of the then Home Minister, Shri Lal Bahadur, you would find that that speech stands in sharn contrast to what the hon. Home Minister said in support of it today, about the continuance of the emergency.

Madam, what was the case of Shri Shastri at that time? He was asking for emergency powers because the situation was grave indeed and the Proclamation said so. At that time the Chinese forces were advancing in huge numbers, as you know, into our territory. Today it is not so Naturally there is a difference in the situation whatever else you may say. The thing which exercised the mind at that time was precisely the situation, when the Chinese forces were coming and we had to deal with the situation in the sense of army movements and so on. It was at that time not a question of defence production or defence preparation as such. It was a question of moving the supplies quickly, moving the Armed Forces quickly, taking prompt action, without waiting for any kind of delays, procedural or administrative. Then there was justification. At that time also similar arguments were given. That was the substance of the arguments which called for, according to the Government, the emergency powers. And we gave the emergency powers, all of us. At that time we were all unanimous. Today there is division. Today you can see there is no unanimity over this matter. It may be that that side has more votes. None the less there is division today. That also is an objective reflection of the situation that prevails in the country.

Madam, when Lal Bahadurji, came here the other day he asked us to think over the problem. He said the dispute was hanging fire indefinitely and some way should be found to solve it since we are dedicated to the cause of peace. Therefore, we should apply our mind to some peaceful solution of the problem. Earlier when Premier Khrushchev made the proposal to renounce war for settling territorial disputes, we supported it. And in that background the Minister without Portfolio said this thing to which I have referred. Now would he have said this thing in November 1962 or December 1962 or even January or February 1963? He would not have said it. Even though the cease-fire had come, he would not have said it in November or December 1962 or even in January or February 1963, for the simple reason that things were not still clear in the mind, it was not clear which way the things were moving There were still very positive apprehensions of a flare-up which might have necessitated the movement of Armed Forces and other things. Today he does not come to say this thing. And I must remind the hon. Mem-

bers who spoke on the November Resolution of 1962 that after the Colombo Proposals we passed another Resolution also. You will remember that when we passed that Resolution we passed it on the ground that it was something different from what had been stated in the Resolution passed in November.

Therefore, it is not as if we are today reviewing the situation. We are actually reviewing the situation from time to time. In the meanwhile we had actually passed two resolutions, one at the time of the invasion and another after the Colombo Proposals had been announced and which we had accepted in toto. Now the situation has developed further but in a better direction. Let us not try to deceive ourselves by thinking that it is not so. All other measures that you had taken for the emergency situation, many other measures, have been withdrawn—the restrictions on production, curb on allocation of funds to the various Ministries, etc We get documents and letters saying that the cut that was imposed in view of the emergency has been restored. Good. It has been restored. In the production sphere, certain curbs were made in order to divert the productive energy to some other channel. These have been restored too. The other day I was reading that now the cement producers will be getting something more, which was restricted or restrained. Therefore all these things happen. By-elections are taking place in the normal way. Therefore this improvement of situation has not been in relation to the border itself. If it were not so, I would have been hard put to defend my position and to sponser my case here. If you take the speeches of the Government leaders, you will find the same thing, not here to-day but they call press conferences and make speeches and in the speeches also they say the same thing. I think we would not be fair to ourselves if we wanted to make out as if it is the same as in November-December 1962. It is not so. From our behaviour, from the various measures that we have withdrawn meanwhile in the intervening period and also because of other developments noted by us in our speeches, we have come to the conclusion that the situation has improved. I think there is no disunity in the country on this matter but why create an artificial divergence with regard to the assessment of the objective situation simply because the Government want the emergency powers to continue? Now here you say 'no fighting for some time'. It is not for some time, for sixteen months there is no fighting. That is very important, a material point in the situation. The emergency was declared not because of a mere threat but because of a grave threat as a result of external aggression, as you put it in the declaration itself. Today you cannot say, whatever may be your assessment with regard to other matters or your assessment of intentions or other things. You do not say this. Therefore I think it has to be viewed from that angle. After our debate last time, the Indian Express wrote an editorial and it said: "Where is the emergency"? That was the title.

4 P.M.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: That is a capitalist paper.

SHRI BHUPESH GUPTA: It wrote on 12th February:

> "But there can be no two opinions that to-day, 15 months after its proclamation, the emergency lies dead on the floor and that all that it needs is a decent burial."

This is what the Indian Express wrote. Then it went on to say:

> "Apart from the prevailing tension with Pakistan on the one hand, and China on the other, it cannot in all conscience be claimed by the Government that the threat to the country's security, however potential is immediate."

[Shri Bhupesh Gupta.]

The third point this paper made was:

> "It is to be hoped that when the Rajya Sabha debate on the subject is resumed a fortnight hence, Home Minister Nanda will take a realistic view of the situation."

This is what was written. Other editorials have also appeared. I have got a subsequent editorial from the *'Times of India'* on the President's Address which was written also after the emergency on 'Incompetence'—that was the title. They are also making fun of the proposed Eighteenth Amendment Bill and related matters connected with the emergency. Therefore other papers also wrote like that. I am not giving the quotations from the paper because it is well known in the country that the press has been reacting to it in a particular way. It shows that the volume of public opinion is against it. Do you mean to say that all of us on this question, Mr. Goenka's paper, Mr. Sahu Jain's paper and all other papers, have gone wrong? No. Understand this position. You take sometimes these publications as signs of public opinion. Therefore I say, there is no fighting today for the last 16 months. There is no fight and we should feel happy about it. Mr. Krishan Dutt was brandishing his sword but his Prime Minister is not doing it. I do not know why he is doing it Certainly do not try to put your policy to discredit. I do not think the Prime Minister will like or even Mr Nanda will like it. Even while speaking on this subject he did not say that the danger has increased. *(Interruptions)*. Yes, Pakistan has got in now. Then say that the Pakistani thing is there. Issue another proclamation, make another speech, start it all afresh

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Very funny argument.

SHRI BHUPESH GUPTA: But the emergency was proclaimed to deal with a situation arising out of a certain external aggression, in certain parts of our country. It was not because of the fact that Pakistan was receiving huge arms aid from the U.S.A. If that was so, then we should have proclaimed an emergency here as soon as the Arms Aid Agreement between Pakistan and the U.S.A. was signed in 1954. We did not do it. In fact we did not declare an emergency in the whole country even in 1948 when one-fourth or one-third of Kashmir was taken. Even to-day, between 1948 and 1962, in that period, aggression had continued there in one-third of Jammu and Kashmir embracing a population of one million people—arms had been accumulated there under the Military Pact Everything was there which constituted a threat that way but you did not declare a state of emergency. In fact we did not discuss this matter at all from the point of view of proclamation of emergency in this House. The whole thing was felt necessary because of the development in 1962 October-November. Let us see whether from that angle it is there or whether the situation has changed for the better. It has changed for the better, there is no doubt about it. Everybody says that the emergency now remains in force only for use of the D.I.R against the Opposition or some such thing. Therefore I cannot agree. Is this the assessment of political leadership of the country, of the Government that they are expecting an immediate attack, a resumption of military operations? No, it is not so. Then the picture would have been different, then the picture would have entirely changed, the attitude would have been different and many things would have been done. Therefore you are not even making that assessment. Whatever you may say here to score a debating point, your assessment of the situation is, whether you are right or wrong is a different matter, that the situation has improved from the point of view of the immediate threat of resumption of armed aggression.

Therefore I say that is not right. Here Mr. Nanda gave so many things about lands and all that Now you see

what he says. It is used for military acquisition and requisitioning of lands but actually they are derequisitioning lands which they took on the declaration of the emergency. They are passing orders derequisitioning them. We know this. Therefore you cannot blow hot and cold. If we say that for the acquiring of land for firing practice we need the emergency powers, people will laugh at us as if in England, France and other countries people do not have artillery or firing practice at all. They do not have their children shooting air-guns in their backyards. They too have artillery guns as we have and they do practise but they do not need emergency powers for that. These are, therefore, lame excuses. The only excuse is this that the Congress Party and the Government need the emergency in order to persecute the people, whatever they may say here. Here I was pointing out Prof. Lal's 'Gur Satyagraha'. He was bringing some gur to Delhi. He was apprehended under the D.I.R. and put in jail. Which border was he threatening? I must know it from the Government.

SHRI A. B. VAJPAYEE: U.P.- Delhi border.

SHRI BHUPESH GUPTA: U.P.- Delhi border was threatened by Prof. Lal carrying half a seer of gur? There should be a limit to a ridiculous approach to public affairs. This is what I say. Now anybody you may find whom you want to arrest for the defence of the country under the D.I.R.

Now, this is all absolutely wrong. Actually, they have no case. Emergency means more power for the bureaucracy, emergency means more power for the Ministers, emergency means more power to issue threats to the democratic rights and liberties of the people, emergency means a sword in the hands of the ruling party to brandish over the heads of the opposition parties and emergency means that when the elections take place you can go and tell the people that if they voted against you, then the Defence of India Rules would be used as has been done in some parts of the country. This is called emergency. Have you taken emergency powers for increasing production? Have you used it for controlling prices? On every count you have failed. You should not only revoke this emergency but should pay compensation to the country for having misused power and having failed in this manner. That is what I say. There should be some sense of proportion. We do not need all these things for increasing agricultural production, which has gone down like anything. *Everything has gone down. Almost* all the commodities have shown a decline in production. You could not compel them to improve the production; you could not use the emergency powers to compel the employers to discharge their responsibilities. You have miserably failed in that sphere but when it came to the workers and the legitimate demands and rights of the workers, you had used these powers.

Madam Deputy Chairman, some people have said that I speak because some of our people are in jail. Naturally I am much concerned about it Even today we have got fourteen of our comrades in jail in Maharashtra including Com. Ranadive, a member of the Central Council, Mr. Parulekar, another member of the National Council and Mrs. Parulekar who is a veteran woman worker of Maharashtra. They are all in jail and three times they were released because the orders were found not to be valid but everytime they were released, instead of releasing them, Government had them rearrested by what they called removal of the technical error. The High Court says that their detention is illegal but again the State Government passes the same order. Now, is that the way to treat the people? Having failed in this, they are doing something more. In Uttar Pradesh, six people are in detention; in Bengal there are two people in detention, belonging to our Party, and in

[Shri Bhupesh Gupta.]

Tripura twentynine people, the entire opposition, is in jail. I have got a telegram here which says that the two M.Ps. from Tripura lodged in Hazaribagh jail are on hungerstrike. They were here at that time and within four days of their reaching their place, they were arrested. I should like the Government to prove anything against them but they have nothing. The entire opposition is in jail; who is, I would like to know, threatening Tripura at the moment. Tripura is threatened by something else, some intrusion there by the Pakistani armed forces. Are you arresting them for that also? I should like to know this. Are our comrades in Tripura in prison because something has developed between Pakistan and India? Then, say so. Our only crime was that in the Third General Elections, we captured both the Lok Sabha Seats from Tripura forming fiftyone per cent. of the votes, the majority of the votes, and in the Assembly we have just the same number. All the leaders of Tripura are in jail today.

This is not the only ground on which I demand revocation of emergency even though that in itself would be an important enough reason. I am glad Mr. Arjun Arora and Tariq supported the release of the detenus. Emergency, I say, should be revoked for the sake of democracy, for the sake of constitutional principles, for the sake of goodness in public life, for public morality. I think that if they believe in continuing this kind of thing and develop a habit of emergency, there will be less and less of difference between us and the dictatorial regimes, militarist regimes which we condemn, and we shall be more or less, acclimatised as Mr. Hare Krushna Mahtab said in the other House, to a regime of negation of democracy. Therfore, I plead with this House that this emergency should be ended. There is no need for it from the point of view of the country and certainly it needs to be revoked from the point of view of the country, democracy and our public life.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"This House is of opinion that having regard to the improved situation in the country the state of emergency should now be ended."

The motion was negatived.

RESOLUTION *RE* APPOINTMENT OF A COMMISSION ON AGRICULTURE

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Madam, with your permission, I would like to move the following Resolution:

"This House is of opinion that Government should appoint a Commission on Agriculture (on the pattern of the Royal Commission on Agriculture of 1926-28) consisting of members representing both Houses of Parliament and experts on agriculture to enquire into the problems of agricultural research, agricultural development and agricultural education in the country, with particular reference to soils, implements, manures, seeds, irrigation, pesticides, improvement of cattle for more milk, sheep, poultry and other economic livestock, and to report on the ways and means of catching up with the progress of other advanced countries, especially in the matter of agricultural productivity."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair]

Mr. Vice-Chairman, it is well known that agriculture is the premier industry of India. Nearly seventy or eighty per cent. of the people are following the agricultural occupation and more than eighty to eighty-five per cent. of the people are depending directly or indirectly upon agriculture. Therefore, if agriculture shows any setback in its development, in its growth, then that will be the greatest tragedy of this country. Therefore, it